

रुह कंपा देने वाली भगदड़

subahsaverenews@gmail.com

facebook.com/subahsaverenews

www.subahsavere.news

twitter.com/subahsaverenews

सुप्रभात

जाते जाते कह गया बसंत
प्रेम का होगा दारुण अंत
सुन कर मैं हँस दिया कंत
जाते जाते कह गया शिशिर
पीले पात ना हरियाते फिर
हँसी अधर पर फिर आयी धिर
मुझे पता था यह होना है
पाने का मतलब खोना है
कल्पों का दुःख
फिर भी मैं तो झेल गया
रस्ते के पर्वत को भी टेल गया
मुझे पता है जीवन का सच
भले मिटे ,फिर भी तू रच
पल भर का भी प्यार मिले तो
सदियां रहती है जीवंत
मैं इसीलिये
हँस दिया कंत।
- गोविंद गुंजन

जीआईएस में ओडीओपी एक्स-पो से लोकल उत्पादों को मिलेगा ग्लोबल मंच : मुख्यमंत्री

भोपाल (नप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि 'एक जिला-एक उत्पाद' हमारे कारीगरों और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। 'ग्लोबल इन्वेस्टरर्स समिट में एक्स-पो माध्यम से हम अपने स्थानीय उत्पादों को वैश्विक मंच देने जा रहे हैं, जिससे प्रदेश के उद्योगों, विशेष रूप से हस्तशिल्प और कृषि उत्पादों को नई पहचान मिलेगी। यह एक्स-पो न केवल हमारे कारीगरों के कौशल को प्रदर्शित करेगा, बल्कि उन्हें नए व्यावसायिक अवसर भी प्रदान करेगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि भोपाल में आयोजित होने वाली 2 दिवसीय 'ग्लोबल इन्वेस्टरर्स समिट में 'एक जिला-एक उत्पाद' एक्स-पो प्रदेश के पारंपरिक उद्योगों और हस्तशिल्प को वैश्विक मंच प्रदान करेगा। इसमें मध्यप्रदेश के विभिन्न जिलों के विशिष्ट उत्पादों को प्रदर्शित किया जाएगा, जिससे स्थानीय शिल्प, कृषि और खाद्य उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पहचान मिलेगी।



ओडीओपी ज़ोन- परंपरा और नवाचार का संगम

एक्स-पो में प्रदेश के 38 ओडीओपी उत्पादों के लिए विशेष स्टॉल लगाए जाएंगे, जिन्हें लाइव कार्डेंटर और प्रोसेस कार्डेंटर में विभाजित किया गया है। लाइव कार्डेंटर में बाघ प्रिंट, जरी जर्दोजी, बाटिक प्रिंट, कालीन, चंदेरी साड़ी, बांस, बलुआ पत्थर और कपड़े की जैकेट जैसे आठ प्रमुख उत्पादों के निर्माण की प्रक्रिया को कारीगरों द्वारा लाइव प्रस्तुत किया जाएगा। खास बात यह है कि प्रतिनिधि और अतिथि कारीगरों के मार्गदर्शन में खुद भी इन उत्पादों को बनाने का अनुभव ले सकेंगे।

‘कुम्हार पुरा’ और ‘टेक्निकल ज़ोन’

मानव संग्रहालय में मिट्टी के बर्तन और धातु कला के लाइव कार्डेंटर भी आकर्षण का केंद्र होंगे।

खाद्य और कृषि उत्पादों की झलक

एक्स-पो में खाद्य, मसाले और फलों से जुड़े 32 ओडीओपी उत्पादों के स्टॉल पर उनकी निर्माण प्रक्रिया के साथ प्रदर्शित किया जाएगा। यहाँ प्रतिनिधि इन उत्पादों को न केवल देख और समझ सकेंगे, बल्कि उन्हें खरीद भी पाएंगे। साथ ही 16 लाइव कार्डेंटरों पर मध्यप्रदेश की पारंपरिक कला और शिल्प का प्रदर्शन होगा, जहाँ अतिथि स्वयं इस प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे।

चुनाव की ‘रेवड़ी’ में ‘पैरासाइट्स’ बनाने वाले विषाणु

लो कसभा और विधानसभा चुनाव में सियासी पार्टियों द्वारा बहुतायत से इस्तेमाल होने वाले 'रेवड़ी' 'फ्रीबीज' या 'खैरात' जैसे बदनाम सियासी औजार एवं उनके इस्तेमाल के अधिकार अब केन्द्र और विभिन्न प्रदेशों की सरकारों की हिरासत से निकाल कर सुप्रीम कोर्ट की न्यायिक-हिरासत में आ गए हैं। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इनके इस्तेमाल पर कोई रोक नहीं लगाई है, फिर भी सार्वजनिक और संवैधानिक नैतिकता के तकाजे हैं कि अब सरकारें चुनाव जीतने के लिए रेवड़ी अथवा फ्रीबीज का उपयोग सुप्रीम कोर्ट की न्यायिक समीक्षा के बाद ही करें। रेवड़ी कल्चर के मामले में अपनी ताजा टिप्पणी में सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार 12 फरवरी 25 को मतदान के पहले चुनाव जीतने के लिए मुफ्त चीजें बांटने के मामले में राजनीतिक दलों को जबरदस्त फटकार लगाई है। उसका मंतव्य है कि सरकारें चुनाव में रेवड़ियां बांटकर समाज के बड़े तबके को 'पैरासाइट्स' या परजीवी बनाने वाले विषाणु बांट रही हैं।

सियासी दलों की इन प्रवृत्तियों की आलोचना करते हुए सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह ने कहा कि आम लोगों को राष्ट्रीय विकास की मुख्य धारा में लाने के बजाय समाज के लिए एक परजीवी (पैरासाइट्स) पैदा करने का यह राजनीतिक उपक्रम राष्ट्र के लिए आत्मघाती सिद्ध हो रहा है। बेहतर होगा कि ऐसे लोगों को मुख्य धारा का हिस्सा बनाकर राष्ट्रीय विकास में उनकी भागीदारी सुनिश्चित की जाए। जस्टिस बीआर गवई ने कहा कि दुर्भाग्यवश चुनाव के ठीक पहले घोषित की जाने वाली लाइली बहना जैसी मुफ्त की

योजनाओं के कारण लोग काम करने को तैयार नहीं होते हैं।

सुप्रीम कोर्ट शहरी क्षेत्रों में बेघर लोगों के आश्रय के अधिकार से संबंधित मामलों में सुनवाई कर रहा था। याचियों के वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि लोग काम करना चाहते हैं, बशर्ते उनके पास काम हो। इसके जवाब में जस्टिस ने कहा कि आपको एकतरफा जानकारी है। मैं कृषक परिवार से आता हूँ। चुनाव के पहले घोषित मुफ्त योजनाओं की वजह से खेतों में काम करने के लिए मजदूर नहीं मिलते हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने फ्रीबीज को लेकर यह पहली बार सख्त टिप्पणी नहीं की है। 9 दिसम्बर, 2024 को भी वह केन्द्र सरकार के मुफ्त राशन बांटने पर लताड़ चुका है। कोर्ट ने पूछा था कि मुफ्त राशन कब तक बांटा जाएगा ? सरकार रोजगार के अवसर पैदा क्यों नहीं कर रही है? केन्द्र की जानकारी के अनुसार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत 81 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज बांटा जा रहा है। वैसे सुप्रीम कोर्ट फ्रीबीज या रेवड़ी-कल्चर पर दो मुख्य याचिकाओं पर विचार कर रहा है। एक याचिकाकर्ता शशांक जे. श्रीधर ने अक्टूबर 2024 में सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत चुनाव के पहले मुफ्त योजनाओं की घोषणाओं को वोट के लिए रिश्त माना जाए।

बीजेपी नेता अश्विन उपाध्याय ने जनवरी 2022 में दायर अपनी याचिका में मांग की है कि चुनाव आयोग ऐसी पार्टियों की मान्यता तुरंत रद्द करे। इस मांग पर चुनाव आयोग ने हाथ झाड़ते हुए कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ही फ्रीबीज स्कीम को परिभाषित करे। फ्रीबीज पर सियासी

दलों की नीतियों को रेगुलेट करना चुनाव आयोग के अधिकार में नहीं है। चुनाव से पहले फ्रीबीज का वादा करना और चुनाव के बाद उसे लागू करना, पार्टियों का नीतिगत फैसला होता है। इस बारे में नियम बनाए बिना कोई भी कार्रवाई करना चुनाव आयोग की शक्तियों का दुरुपयोग करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ही तय करे कि फ्री स्कीम क्या है और क्या नहीं...? इसके बाद ही हम इसे लागू कर सकेंगे।

चुनाव जीतने के खास औजारों के रूप में प्रचलित 'रेवड़ी' 'फ्रीबीज' या 'खैरात' सामाजिक क्षेत्र में बदनाम शब्दों में शुमार होने लगे हैं। चुनाव के वक्त समाज में कमजोर वर्ग की मदद अथवा सामाजिक न्याय के नाम पर रेवड़ी, फ्रीबीज या खैरात का अंतहीन सिलसिला अब आरक्षण की तरह ही विवादास्पद होता जा रहा है। मोटे तौर पर ये सुविधाएं सियासी पार्टियों द्वारा चुनाव जीतने के लिए मतदाताओं को दी जाने वाली राजनीतिक रिश्त को नीतियों का जामा पहनाने का शगल है। भाजपा, कांग्रेस समेत सभी पार्टियाँ रेवड़ी के रूप में राजनीतिक रिश्त देने की घनघोर आरोपी हैं। भारत के संवैधानिक गणतंत्र की सैद्धांतिक पृष्ठभूमि में लोकतंत्र की मान्य परम्पराओं की खिल्ली उड़ाने वाले इस 'फाउल-प्ले' पर चुनाव-प्रक्रियाओं के नियामक केन्द्रीय चुनाव आयोग की नेत्रहीनता और चुनाव आयुक्त की मूक-बधिरता हैरत पैदा करने वाली है।

फ्रीबीज योजनाओं के कारण विभिन्न राज्यों की अर्थ व्यवस्था चरमरा रही है। देश के सबसे अधिक कर्ज में डूबे राज्यों में तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बंगाल और कर्नाटक पर सबसे अधिक कर्ज है। रिजर्व बैंक की रिपोर्ट के

अनुसार 2024 में राज्यों पर 75 लाख करोड़ कर्ज का आंकड़ा 2025 में बढ़कर 83.31 लाख करोड़ हो जाएगा। इन परिस्थितियों का सीधा असर राज्यों के बुनियादी विकास से जुड़ी योजनाओं पर पड़ता है। नीति आयोग का कहना है कि जो राज्य बहुत अधिक मुफ्त चीजें वितरित करने वाले कर्ज के जाल में उलझ कर पिछड़ जाते हैं।

लोकसभा और विधानसभा चुनाव जीतने के लिए जारी मुफ्तखोरी की राजनीतिक प्रतिस्पर्धा देश के लिए आत्मघाती है। राजनीतिक दलों को चुनाव जीतने के लिए सुविधाओं की रेवड़ियों के रूप में आसान नुस्खा मिल गया है। इसकी बानगी पिछले लोकसभा और विधानसभा चुनावों में सियासी दलों के घोषणा-पत्रों में स्पष्ट नजर आती है। पहले चुनाव राष्ट्रवाद, राष्ट्रीय सुरक्षा और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर लड़े जाते थे। देश की आर्थिक नीतियां प्रचार के केन्द्र में होती थी लेकिन अब पैटर्न बदल गया है।

वैसे तो फ्रीबीज योजनाओं का इतिहास पुराना है, लेकिन दस साल पहले अस्तित्व में आई आम आदमी पार्टी ने बिजली-पानी की मुफ्तखोरी को चुनावी रणनीति में जिस तरह से इस्तेमाल किया, वह सभी पार्टियों के लिए रोड-मैप बन गया। इसके बाद मध्य प्रदेश में लाइली बहना योजना ने चुनावी जीत में उछेक का काम किया। इसके बाद देश के लगभग सभी विधानसभा चुनावों में नीतियों के बजाय फ्रीबीज योजनाओं के पिंटों खुलने लगे। भारतीय राजनीति में जनता को मुफ्तखोर बनाकर वोट हासिल करने की प्रवृत्ति देश को गंभीर संकट की ओर ढ़कल रही है। फ्रीबीज के जरिए सत्ता हासिल करने की राह भले ही आसान हो, लेकिन इसके पीछे उठने वाले कैक्टस विकास की राहों को कंटीला बना रहे हैं।

रुह कंपा देने वाली भगदड़

● नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में जान गंवाने वालों की आपबीती

● डुबकी लगाने का था सपना, शव ले जाने को हुए मजबूर

● परिवारों में पसरा मातम, रो-रो कर लोगों का है बुरा हाल



नई दिल्ली (एजेंसी)। शनिवार रात को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मचने की वजह से 18 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, 35 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। इन यात्रियों में ज्यादातर लोग महाकुंभ जाने की होड़ में थे, सभी प्रयागराज पहुंचाना जाना चाहते थे। लेकिन रेलवे प्रशासन की अव्यवस्था, कुछ ट्रेनों की देरी के चलने की वजह से भगदड़ जैसी स्थिति पैदा हो गई और इतने लोगों की जान

गई। इस समय कई परिवारों में मातम पसरा हुआ है, रो-रो कर लोगों का बुरा हाल है। लोग अपनी को खोकर बुरी तरह टूट चुके हैं, सपना महाकुंभ में डुबकी लगाने का देखा था, लेकिन अब अपनों के शव ले जाने को मजबूर दिखाई दे रहे हैं।

सरकार ने अपनी तरफ से आर्थिक सहायता का ऐलान जरूर कर दिया है, लेकिन मृतक के परिवार वाले इससे संतुष्ट नहीं हैं, वे असल न्याय की बात कर रहे हैं।



जांच कमेटी बनी, सीसीटीवी फुटेज सील; दिल्ली-एनसीआर के टीटी नई दिल्ली स्टेशन बुलाए

इस समय 18 लोगों की पूरी लिस्ट भी सामने आ चुकी है जिनकी इस भगदड़ में जान गई। ये सभी महाकुंभ जाने के लिए निकले थे, लेकिन अब दुनिया को ही अलविदा कह चुके हैं। जानकारी के लिए बता दें कि 18 लोगों की मौत हुई है उसमें 9 महिलाएं, 4 पुरुष और 5 बच्चे शामिल हैं। इस घटना की वजह प्रशासनिक लापरवाही और भीड़ प्रबंधन की चूक बताई

जा रही है। जानकारों के मुताबिक ये हदसा टाला जा सकता था क्योंकि जब प्रति घंटे करीब 1500 टिकट बेचे जा रहे थे तभी प्रशासन को एक्शन में आ जाना चाहिए था। जनरल बोली की सीमित जगह के बावजूद जरूरत से ज्यादा टिकट बेचे गए। इस हदसे का सबसे बड़ा और मुख्य कारण रेलवे द्वारा प्लेटफार्म बदलने की अचानक की गई घोषणा थी।

हादसे के लिए सरकार को खूब तीखा सुना रहा विपक्ष

नई दिल्ली (एजेंसी)। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ के मामले से सियासी पारा चढ़ गया है। विपक्षी दल केंद्र सरकार पर हमलावर हैं। कांग्रेस ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ में हुई मौतों के बारे में सरकार पर रविवार को सच्चाई छिपाने का आरोप लगाया और कहा कि इससे एक बार फिर रेलवे की 'विफलता' और सरकार की 'असवेदनशीलता' उजागर हुई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि महाकुंभ के लिए प्रयागराज जाने वाले श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या को देखते हुए स्टेशन पर बेहतर व्यवस्था की जानी चाहिए थी। यह घटना एक बार फिर रेलवे की विफलता बताती है।



घंटों जाम में फंसे हैं लोग, सेना ने संभाला मोर्चा

प्रयागराज में भीषण जाम, चरमसाईं ट्रैफिक व्यवस्था

ब्रिज पर अल्लोपीबाग चौराहे से लेकर अंदाबा मोड़ तक गाड़ियां फंसी हैं। जबकि फाफामऊ पुल पर तेलियरगंज से लेकर प्रतापगढ़ और लखनऊ रोड पर कई किमी तक रास्ते में लोग फंसे हैं। बता दें कि प्रयागराज में जाम को लेकर लगातार शिकायतें आ रही हैं। दो दिन पहले ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़े अधिकारियों के साथ बैठक की थी और वरिष्ठ अधिकारियों को सड़कों पर उतरने का निर्देश दिया था। उन्होंने साफ कहा था कि यह सुनिश्चित करें कि किसी भी दशा में कहीं जाम नहीं लगना चाहिए।



दिल्ली के नए सीएम का नाम आज तय होगा, भाजपा ने विधायक दल की बैठक बुलाई, शपथ 18 फरवरी को संभल

नई दिल्ली (एजेंसी)। दिल्ली में नए सीएम का नाम सोमवार को तय हो जाएगा। प्रदेश कार्यालय में दोपहर करीब 3 बजे विधायक दल की बैठक बुलाई गई है। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने मीडिया को इसकी जानकारी दी है।

वहीं सूत्रों ने बताया कि बैठक के लिए ऑब्जर्वर के नाम देर रात या आज सामने आ जाएंगे। बैठक में दिल्ली के सभी सात सांसद भी मौजूद रहेंगे। जबकि शपथ ग्रहण 18 फरवरी को रामलीला मैदान में हो सकती है। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्ड पहले ही साफ कर चुके हैं कि मुख्यमंत्री निर्वाचित विधायकों में से होगा। बैठक में कैबिनेट मंत्रियों के नाम की भी घोषणा हो सकती है।

अमेरिका ने 116 और भारतीयों को जबरन लौटाया

जबर्न लौटाया पुरुषों को हथकड़ी-बैडियां लगाईं,अमृतसर एयरपोर्ट से 5 घंटे बाद घर भेजा

अमृतसर (एजेंसी)। अमेरिका में अवैध तरीके से रह रहे 116 और भारतीयों को जबरन भारत भेज दिया गया। अमेरिकी एयरफोर्स का विमान ग्लोबमास्टर शनिवार देर रात 11.30 बजे अमृतसर एयरपोर्ट पर उतरा। इस बार महिलाओं-बच्चों को छोड़कर सभी पुरुषों को हाथों में हथकड़ियां और पैरों में बैडियां डालकर विमान में बैठाया गया था। एयरपोर्ट पर ही उनके परिवार से मुलाकात कराई गई। करीब 5 घंटे की वैरिफिकेशन के बाद पुलिस की गाड़ियों में सभी को घर छोड़ा गया। इस दौरान किसी को भी मीडिया से बातचीत नहीं करने दी गई। इससे पहले 5



फरवरी को 104 अप्रवासी भारतीयों को जबरन लौटाया जा चुका है। इनमें बच्चों को छोड़कर महिलाओं-पुरुषों को हथकड़ियों और बैडियों में जकड़कर लाया गया था। इस तरह अब तक 220 अवैध अप्रवासी भारतीयों को भारत भेजा जा चुका है। इस विमान में डिपोर्ट हुए होशियारपुर के दलजीत सिंह ने हथकड़ियां-बैडियां लगाने की पुष्टि की। उन्होंने कहा- हमारे हाथ बंधे थे और पैरों में जंजीरें डाली गई थीं। वह डकी रूट से अमेरिका पहुंचा था। वहीं डिपोर्ट होकर आए चचेरे भाइयों संदीप और प्रदीप को पटियाला पुलिस ने डिटेन किया है। उनसे जून 2023 में दर्ज कल केस के मामले में पूछताछ की जा रही है।

कर्नाटक कांग्रेस में एक बार फिर मचा घमासान

डीके शिवकुमार को प्रदेश अध्यक्ष से हटाने की मांग से हटाने की मांग

बेंगलुरु (एजेंसी)। कर्नाटक कांग्रेस में नेतृत्व परिवर्तन को लेकर मांग तेज हो गई है। पार्टी के कई नेता राज्य के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाने की मांग कर रहे हैं। राज्य के लोक निर्माण मंत्री सतीश जायकीहोली ने मल्लिकार्जुन खड्गे और केंसी वेणुगोपाल से मुलाकात करके प्रदेश अध्यक्ष बदलने की मांग की है। वे इस पद के



मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक, यह बदलाव साल के अंत तक हो सकता है। इस साल उन्हें सीएम बनाए जाने की भी संभावना है। हालांकि, शिवकुमार ने इस मामले पर अब तक चुपी साध रखी है। वहीं, कैबिनेट मंत्री केएन राजन्ना ने कहा कि शिवकुमार को लोकसभा चुनाव तक प्रदेश अध्यक्ष बनाए रहने की बात हुई थी। लेकिन सिद्धारमैया ढाई साल तक ही मुख्यमंत्री होंगे, यह साफ नहीं है। कांग्रेस महासचिव केंसी वेणुगोपाल ने 2023 में बयान दिया था।

सुबह सवेरे

भोपाल

ठंड से मिली राहत, बारिश होने की संभावना

हिमाचल से लेकर बंगाल तक बरसेंगे बदरा,आईएमडी का अलर्ट



जीआईएस में इतने रजिस्ट्रेशन कि बंद करनी पड़ी विंडो

सीटिंग प्लान में भी बदलाव ; जिस डोम में पीएम मोदी रहेंगे, वहां 3000 मेहमानों को ही एंट्री

भोपाल (नप्र)। मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में 24-25 फरवरी को ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट (सीआईएस) होगी। इसमें देश के शीर्ष 50 बड़े उद्योगपति शामिल होंगे। जिस डोम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहेंगे, वहां सिर्फ 3 हजार उद्योगपतियों को ही एंट्री मिलेगी। समिट के लिए 30 हजार रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। 8 हजार रजिस्ट्रेशन तो आखिरी 3 दिन में ही हुए हैं। इस कारण एक दिन पहले ही रजिस्ट्रेशन बंद करने पड़े। ऐसे में अब सीटिंग प्लान में बदलाव किया जा रहा है। एमपी स्टेड इंस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के मुताबिक, मानव संग्रहालय में 24 फरवरी की सुबह 10 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समिट का उद्घाटन करेंगे। डेढ़ घंटा चलने वाले कार्यक्रम में 5 हजार उद्योगपतियों को ही एंट्री दी जाएगी। इनमें से 3 हजार लोग डोम और बाकी हॉल में रहेंगे। कार्यक्रम के बाद 10 हजार को और एंट्री दी जाएगी। इस तरह एक दिन में 15 हजार उद्योगपतियों को एंट्री देने का प्लान है।

ऐसे मिलेगी उद्योगपतियों को एंट्री- ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2 दिन की है। रजिस्ट्रेशन कराने वाले उद्योगपति अलग-अलग रंग के पास के जरिए दो दिन तक समिट में जा सकेंगे। 15 हजार उद्योगपतियों को पहले ही दिन एंट्री दे दी जाएगी। ऐसे में सवाल है कि बाकी 15 हजार का क्या होगा? इस बारे में अप्सरों का कहना है कि कंपनी के एगुअल टर्नओवर के हिसाब से एंट्री देने का प्लान है। पहले दिन ऐसे उद्योगपतियों को बुलाया जाएगा, जिनकी कंपनी का टर्नओवर और इन्वेस्ट करने का मकसद स्पष्ट हो। बचे 15 हजार उद्योगपतियों को अगले दिन 25 फरवरी को एंट्री दी जा सकती है।

भाजपा को नया अध्यक्ष मिलने की बढ़ गई तारीख

कब तक मिलेगा जेपी नड्डा का विकल्प, हो रही तलाश

नई दिल्ली (एजेंसी)। जेपी नड्डा बीते करीब 6 सालों से भाजपा के लगातार अध्यक्ष बने हुए हैं। उन्हें लोकसभा चुनाव तक के लिए कार्यकाल विस्तार मिला था, लेकिन फिर महाराष्ट्र, हरियाणा जैसे राज्यों के चुनाव के कारण नए अध्यक्ष का चुनाव लटक गया। उम्मीद थी कि जनवरी या फरवरी तक भाजपा को नया अध्यक्ष मिल जाएगा, लेकिन यह फिर से टल गया है। अब कहा जा रहा है कि मार्च में भाजपा को जेपी नड्डा का विकल्प मिल जाएगा। इसकी वजह यह है कि भाजपा के संविधान के अनुसार राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव से पहले कम से कम आधी राज्य इकाइयों के अध्यक्षों का चुनाव हो जाना चाहिए।

वहीं प्रदेश अध्यक्षों के इलेक्शन से पहले जिलाध्यक्ष चुने जाने चाहिए। अब तक कई राज्य ऐसे हैं, जहां जिलाध्यक्ष ही नहीं चुने जा सके हैं और इसके कारण प्रदेश अध्यक्षों का इलेक्शन



अटक है। फिर इसी के कारण राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में भी देरी हो रही है। इसकी एक वजह यह भी रही कि भाजपा ने अपने संगठन की पूरी

चर्च के अंदर मिले मंदिर के अवशेष, शुरू हुई पूजा

केरल का है मामला, अजोखा इतिहास भी आया सामने

तिरुअनंतपुरम (एजेंसी)। केरल में एक चर्च के केंद्र में खुदाई के दौरान मंदिर के अवशेष मिलने के बाद वहां पूजा अर्चना करने की अनुमति दी गई है। केरल के पलायं में एक कैथोलिक चर्च की जमीन पर खुदाई के दौरान प्राचीन मंदिर के अवशेष मिले हैं। इस जगह से शिवलिंग समेत कई धार्मिक चिन्ह सामने आए हैं, जिसके बाद इलाके चर्चा आम हो गई। दिलचस्प बात यह है कि चर्च प्रशासन ने सौहार्द्रपूर्ण रवैया अपनाते हुए हिंदू समुदाय को वहां पूजा अर्चना करने की इजाजत दे दी है। रिपोर्ट के मुताबिक, 1.8 एकड़ की इस जमीन पर जब कसावा (टैपियोका) की खेती के लिए खुदाई हो रही थी, तभी यी अवशेष नजर आए।

पूरे हिंदू समाज को एकजुट करना चाहता है संघ:भागवत

● आरएसएस प्रमुख का वेस्ट बंगाल के बर्धमान रैली में बड़ा बयान

मोहन भागवत ने विविधता में एकता के महत्व पर दिया जोर

बर्धमान (एजेंसी)। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के प्रमुख मोहन भागवत ने दुनिया की विविधता को अपनाने के महत्व पर जोर देते हुए रविवार को कहा कि हिंदू समाज का मानना है कि एकता में ही विविधता समाहित है। बर्धमान के साई ग्राउंड में आरएस एस के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि लोग अक्सर पूछते हैं कि हम केवल हिंदू समाज पर ही ध्यान क्यों देते हैं, और मेरा जवाब है कि देश का जिम्मेदार समाज हिंदू समाज है। आरएसएस चीफ भागवत ने कहा कि आज कोई विशेष कार्यक्रम नहीं है। जो लोग संघ के बारे में नहीं जानते, वे अक्सर सवाल करते हैं कि संघ क्या चाहता है। अगर मुझे जवाब देना होता, तो मैं कहता कि संघ हिंदू समाज को संगठित करना चाहता है, क्योंकि यह देश का जिम्मेदार समाज है।

● भारत में कोई भी सम्राटों और महाराजाओं को याद नहीं करता- भागवत ने कहा कि भारत में कोई भी सम्राटों और महाराजाओं को याद नहीं करता, बल्कि अपने पिता का वचन पुरा करने के उद्देश्य से 14 साल के लिए वनवास जाने वाले राजा (भगवान राम) और उस व्यक्ति (भरत) को याद रखता है जिसने अपने भाई की पादुकाएं सिंहासन पर रख दीं, और वनवास से लौटने पर राज्य उसे राज सौंप दिया। उन्होंने कहा कि ये विशेषताएं भारत को परिभाषित करती हैं। जो लोग इन मूल्यों का पालन करते हैं, वे हिंदू हैं और वे पूरे देश की विविधता को एकजुट रखते हैं। हम ऐसे कार्यों में शामिल नहीं होते जो दूसरों को आहत करते हैं। शासक, प्रशासक और महापुरुष अपना काम करते हैं, लेकिन समाज को राष्ट्र की सेवा के लिए आगे रहना चाहिए।

फतेहपुर सीकरी में इंग्लैंड के पूर्व पीएम ऋषि सुनक

सलीम चिश्ती की दरगाह पर बांधा मज्जत का धागा

आगरा (एजेंसी)। भारत दौर पर आए इंग्लैंड के पूर्व प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने रविवार को फतेहपुर सीकरी स्मारक का दीदार किया। इसके बाद उन्होंने हरजत सलीम चिश्ती की दरगाह पर फूल चढ़ाए और मंत्रत का धागा बांधा। शनिवार को पूर्व प्रधानमंत्री अपने परिवार के साथ ताजमहल का दीदार



किया था। ताजमहल की खूबसूरती के बारे में उन्होंने जमकर कसौद गढ़े थे। इंग्लैंड के पूर्व प्रधानमंत्री ऋषि सुनक परिवार के साथ दो दिवसीय आगरा दौर पर हैं। शनिवार शाम को उन्होंने ताजमहल का दीदार किया था। उनके साथ उनकी पत्नी अक्षता मूर्ति, सास सुधा मूर्ति और उनकी बेटियां कृष्णा एवं अनुष्का भी थीं।

राहुल गांधी की सलाह पर फिर खड़ी हुई नई कांग्रेस

● प्रभारी महासचिवों की तैनाती में 75 फीसदी आरक्षण

नई दिल्ली (एजेंसी)। बीते कई सालों से कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगातार आरक्षण की बात करते रहे हैं। वह आबादी के अनुपात में जातिगत आरक्षण की बात दोहराते रहे हैं, जबकि विपक्ष का कहना रहा है कि राहुल गांधी जो कह रहे हैं, उस पर अमल भी करें। अब राहुल गांधी की पहल पर कांग्रेस में जो 11 राज्यों के प्रभारी बनाए गए हैं, उनमें से 8 नेता उन्हीं वर्गों के हैं, जिन्हें प्राथमिकता देने की बात राहुल गांधी करते रहे हैं। इन नेताओं में 5 यानी करीब आधे ओबीसी वर्ग के हैं तो वहीं एक दलित, एक मुस्लिम, एक आदिवासी शामिल हैं। इसके अलावा तीन नेता सामान्य वर्ग के हैं। इस तरह करीब 75 फीसदी कोटा ओबीसी, एससी-एसटी और अल्पसंख्यकों के लिए रखा गया है। इन नेताओं में अहम

चेहरा भूपेश बघेल हैं, जो पंजाब के प्रभारी महासचिव बने हैं। वह छत्तीसगढ़ के सीएम रह चुके हैं और प्रियंका गांधी से लेकर राहुल तक के करीबी माने



प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। वह ऐसे सवाल करते तो लोग उनकी ही पार्टी के नेताओं की लिस्ट गिना देते थे कि देखिए आपके यहां से किसे महत्व

जाते हैं। राहुल गांधी लोकसभा चुनाव से भी कई महीने पहले से संविधान की कॉपी हाथ में लेकर घूमते रहे हैं। संविधान की कॉपी दिखाते हुए वह कहते हैं कि इसके अनुसार देश के वंचित तबकों को उचित

मिलता है। ऐसे में अब बदली हुई कांग्रेस के साथ राहुल गांधी ने आलोचकों को जवाब देने की कोशिश की है। नए बदलाव के तहत दो राज्यों को महासचिव मिले हैं तो वहीं 9 राज्यों में प्रभारी तैनात किए गए।

सब सोच रखा है तो हमारी जरूरत ही क्या है

चंडीगढ़ (एजेंसी)। अंबाला नगर परिषद के चुनाव में पार्षदों के टिकट बंटवारे को लेकर मची कलह तेज होती जा रही है। अंबाला कैंट से विधायक और भाजपा के वरिष्ठ मंत्री अनिल विज अपने 15 समर्थकों को टिकट न मिलने से भड़के हुए हैं। उनके समर्थकों ने यहां तक कह दिया है कि यदि लोकल यूनिट की बात को खारिज कर हाईकमान के लेवल से ही सब तय हो रहा है तो फिर हमारी जरूरत ही क्या है। एक समर्थक ने कहा कि कुल 32 नामों का ऐलान हुआ है, जिनमें से 15 लोग तो ऐसे हैं, जिनकी सिफारिश स्थानीय स्तर पर किसी भी नेता ने नहीं की थी। इस पर अनिल विज भड़क गए हैं और उनका कहना है कि क्या मैं विदेश चला जाऊं, जब कोई सुनवाई ही नहीं हो रही है।

शुक्रवार को देर रात लिस्ट जारी हुई तो हलचल तेज हो गई। अनिल विज के समर्थक उनके घर पहुंचने लगे। यही नहीं अनिल विज के समर्थकों ने नारेबाजी की शनिवार को भी यह सिलसिला जारी रहा

और अब रविवार को भी उनके यहां समर्थकों का हुजूम उमड़ा पड़ा है। स्थानीय कार्यकर्ता, नेता, बूथ और मंडलों के अध्यक्ष उनसे मिलने पहुंच रहे हैं। खबर है कि स्थानीय यूनिट की तरफ से हाईकमान को एक ईमेल भी भेजा गया है। इसमें टिकट बंटवारे को लेकर असंतोष जाहिर किया गया है। अनिल विज के समर्थकों ने नारेबाजी की भी की है। खासतौर पर उन लोगों के

● आर-पार के मूड में अनिल विज, 'अन्याय' पर भड़के



रेल मंत्री इस्तीफा दें : रघु ठाकुर

भोपाल। लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी के संरक्षक रघु ठाकुर ने कहा है कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जो भगदड़ मची जिसमें अभी तक मीडिया व सोशल मीडिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार पच्चीस के लगभग श्रृद्धालुओं की मृत्यु हो चुकी है अत्यधिक दुखद है। इन निर्दोष श्रृद्धालुओं की मृत्यु की जिम्मेदारी रेलवे और शासन की है। क्या इतनी बड़ी संख्या में भीड़ जमा होने की जानकारी और वह भी देश की राजधानी दिल्ली में केंद्र सरकार के खुफिया तंत्र, रेलमंत्री व रेल के उच्च अधिकारियों को नहीं थी।लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी राष्ट्रपति से अपील करती है कि रेल मंत्री श्रीवैष्णव को बर्खास्त करें क्योंकि उनका विश्वास सार्वजनिक जीवन की नैतिकता में नहीं है और वे कभी भी अपनी नैतिक, वैधानिक, प्रशासनिक जिम्मेदारी नहीं स्वीकारेंगे। ग्रह मंत्री अमित शाह को भी इस खुफिया तंत्र की असफलता को अपनी नैतिक जिम्मेदारी मान कर इस्तीफा देना चाहिए।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन हादसे पर दुःख व्यक्त किया

भोपाल (नप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर अचानक भीड़ बढ़ने से हुए दुर्भाग्यपूर्ण हादसे में लोगों के हलाहत होने पर दुःख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने इस पीड़ादायक घटना से प्रभावित शोक संतप्त परिवारजनों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बाबा महाकाल से दिवंगत आत्माओं को अपने श्रृीचरणों में स्थान एवं शोकाकुल परिजनों को यह असीम कष्ट सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना भी की।

भोपाल में बाइक से गिरे युवक की मौत

दोस्त के साथ चाउमिन खाने निकला था

भोपाल (नप्र)। भोपाल के टीटी नगर इलाके में बाइक से गिरने के बाद युवक की मौत हो गई। हादसा शनिवार रात का है। युवक दोस्त के साथ बाइक पर चाउमिन खाने निकला था। मामले में पुलिस ने मर्ग



कायम कर लिया है। दोस्त के बयानों को दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है।

थाना प्रभारी सुधीर अरजरिया ने बताया कि सागर वर्मा (25) शनिवार देर रात दोस्त के साथ चाउमिन खाने निकला था। दोस्त बाइक चला रहा था और सागर पीछे बैठा था। माता मंदिर चौराहा के पास सागर अचानक बाइक से नीचे गिरा, इससे दोस्त घबरा गया। स्थानीय लोगों की मदद से उसे अस्पताल पहुंचाया। जहां डॉक्टरों ने चेक करने के बाद उसे मृत घोषित कर दिया।

अधिकारी की गाड़ी चलाता था सागर

सागर वल्लभ भवन में किसी अधिकारी की कार चलाता था, इस साल उसकी शादी की तैयारी थी। युवक की मौत से परिजन सदमे में हैं। परिवार में सागर के अलावा उसका एक छोटा भाई है।

फांसी लगाकर कारोबारी ने की खुदकुशी

लोगों ने शव देखकर पुलिस को दी सूचना, जांच शुरू

भोपाल (नप्र)। भोपाल के अशोका गार्डन इलाके में चाय की दुकान का संचालन करने वाले युवक ने शनिवार की रात को दुकान में फांसी लगा ली। सुसाइड नोट नहीं मिलने से खुदकुशी के कारणों का खुलासा नहीं हो सका है। मामले में पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक शुभम सूर्यवंशी (30) अशोक बिहार कॉलोनी में रहता था। आईटीआई के सामने जेके रोड पर चाय की दुकान का संचालन करता था। शनिवार को सुबह दुकान जाने का बोलकर घर से निकला था। हालांकि उसने दुकान को खोला ही नहीं। रात के समय लोगों ने उसके शव को फंदे पर लटका देखा।

माता-पिता का इकलौता बेटा था मृतक युवक

तत्काल मामले की जानकारी पुलिस को दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पीएम के लिए भेज दिया। रविवार की दोपहर को बांडी पीएम के बाद परिजनों को सौंप दी गई है। बताया जा रहा है कि शुभम अविवाहित था और मां पिता का इकलौता बेटा था।

दमोह में रेलवे ट्रैक पर फंसा डंपर दमोह (नप्र)। दमोह में रविवार दोपहर करीब 3~30 बजे बड़ा रेल हादसा टल गया। धरमपुरा रेलवे फाटक पर एक डंपर रेलवे ट्रैक पर फंस गया, जिससे रेल यातायात प्रभावित हुआ। घटना की जानकारी मिलते ही स्टेशन प्रबंधन ने तत्काल कार्रवाई



करते हुए रेलवे ट्रैक के दोनों तरफ लाल झंडा लगाकर यातायात रोक दिया। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए तीन मालगाड़ियों को रोकना पड़ा। स्थानीय लोगों और रेलवे कर्मचारियों ने मिलकर डंपर को निकालने का प्रयास किया। करीब एक घंटे की कड़ी मशकत के बाद ट्रैक्टर की सहायता से डंपर को खींचकर रेलवे ट्रैक से बाहर निकाला गया। डंपर के ट्रैक से हटते ही रेल यातायात पुनः सामान्य हो गया।

म.प्र. लॉजिस्टिक्स पॉलिसी-2025 लिखेगी प्रदेश की समृद्धि का नया अध्याय: मुख्यमंत्री डॉ. यादव

नवाचार से विश्वस्तरीय बनेगा लॉजिस्टिक इन्फ्रास्ट्रक्चर, आपूर्ति होगी आसान, लागत पर लगेगी लगाम

भोपाल (नप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और जीआईएस में जुट रहे निवेशकों को आकर्षित करने राज्य सरकार ने मध्यप्रदेश लॉजिस्टिक्स पॉलिसी-2025 जारी की है। पॉलिसी के नवाचारों से लॉजिस्टिक्स लागत में कमी लाकर आपूर्ति दक्षता को बेहतर बनाएगी। उन्होंने कहा कि पॉलिसी का उद्देश्य प्रदेश में दक्ष, विश्वसनीय और रणनीतिक रूप से स्थाई विश्व स्तरीय लॉजिस्टिक इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास करना है, जिससे वर्ष 2030 तक लॉजिस्टिक लागत को वैश्विक मानकों के अनुरूप कम किया जा सके। इससे प्रदेश घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय व्यवसायों के लिए आकर्षक स्थल बन सकेगा।

मध्यप्रदेश लॉजिस्टिक्स पॉलिसी-2025 प्रदेश के समग्र आर्थिक विकास की दिशा में भी महत्वपूर्ण साबित होगी। यह नीति राज्य को लॉजिस्टिक्स का प्रमुख केंद्र बनाने, निवेशकों को आकर्षित करने और व्यापार को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभाएगी। आगामी वर्षों में इससे मध्यप्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई ऊँचाइयाँ मिलेंगी।

पॉलिसी के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए, राज्य सरकार पोर्ट टर्न अराउंड समय को कम करने पर ध्यान केन्द्रित कर रही है। इससे राज्य की आपूर्ति श्रृंखला की दक्षता को सुधारा जा सकेगा। साथ ही पीसीएस-वन प्रणाली से ई-डिलीवरी आदेशों को पेश किया जाएगा, जिससे लॉजिस्टिक्स प्रक्रियाओं को और अधिक सुव्यवस्थित और पारदर्शी बनाया जा सकेगा। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के लिए डेडिकेटेड लैब बनाई जाएगी, जिससे उत्पाद सुरक्षा नियमों और गुणवत्ता मानकों खरे उतर सकेंगे। रेडियो फ्रीक्वेंसी आईडेंटिफिकेशन डोर (आरएफआईडी) जैसे तकनीकी नवाचार सुरक्षा को बढ़ाएंगे और माल की आवाजाही भी तेज होगी। साथ ही यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म के व्यापार को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभाएगी। आगामी वर्षों में इससे मध्यप्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई ऊँचाइयाँ मिलेंगी।



योजना भी शामिल है, जो ऐसे लॉजिस्टिक्स संचालकों को शीघ्र मंजूरी देगी, जो ग्रीन-ट्रांसपोर्टेशन को अपनाएंगे।

इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास से बढ़ेगी परिवहन दक्षता- अन्तर्राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लॉजिस्टिक ट्रांसपोर्टेशन के योग्य इन्फ्रास्ट्रक्चर विकसित करने के लिए राज्य सरकार 20 से अधिक कार्गो टर्मिनल विकसित कर रही है। इससे लॉजिस्टिक्स नेटवर्क मजबूत होगा। ये टर्मिनल अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित होंगे, जो माल ढुलाई को सुगम बनाएंगे। परिवहन लागत कम होने से व्यवसायियों का लाभ बढ़ेगा और प्रदेश में अधिक निवेश

आकर्षित होगा।

निर्यात विकसित इन्फ्रास्ट्रक्चर-	क्षमता बढ़ाने होगा विशेष	विशेष
लॉजिस्टिक्स पॉलिसी-2025 का एक महत्वपूर्ण अंग	राज्य की निर्यात क्षमता को बढ़ाना भी है। इसके लिए पॉलिसी में निर्यात पार्क विकसित किए जाने के प्रावधान शामिल किये गए हैं। इन पार्कों के विकास को स्टॉप ड्यूटी और	पंजीकरण शुल्क पर 100 प्रतिशत प्रतिपूर्ति प्राप्त होगी, साथ ही इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए अधिकतम 40 करोड़ रुपए अथवा प्रति एकड़ 50 प्रतिशत तक की वित्तीय सहायता भी दी जाएगी। निर्यातकों के लिए सामान्य प्र-संस्करण सुविधाओं की स्थापना को भी प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके लिये परियोजना लागत की 25 प्रतिशत तक अथवा अधिकतम 25 करोड़ रुपए तक वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। पॉलिसी में ग्रीन इंडस्ट्रीलायजेशन को भी प्रोत्साहित किया गया है। इसके लिए अपशिष्ट प्रबंधन की शून्य तरल प्रणालियों

और केंद्रीकृत अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों की स्थापना पर 50 प्रतिशत तक प्रतिपूर्ति प्रदान की जाएगी।

निर्यातकों की भागीदारी बढ़ाने पर जोर- पॉलिसी में निर्यातकों की भागीदारी को बढ़ाने पर जोर दिया गया है। इसके लिए निर्यात विविधीकरण को बढ़ावा, निर्यात-उन्मुख इकाइयों की दक्षता बढ़ाना और सुदृढ़ निर्यातोन्मुख लॉजिस्टिक्स इन्फ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जा रहा है। पॉलिसी के उद्देश्यों में निर्यात की मात्रा बढ़ाना, 'मेड इन मध्यप्रदेश' उत्पादों के निर्यात मूल्य में वृद्धि करना और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में रोजगार के अवसरों का सृजन भी शामिल है।

घरेलू और विदेशी निवेशकों के लिये सुनहरा अवसर- लॉजिस्टिक्स लागत में कमी से व्यापारियों और उद्यमियों को सीधा लाभ होगा। वैयरहाउस, ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स कंपनियों में लाखों नई नौकरियाँ उपलब्ध होंगी। विदेशी और घरेलू निवेशकों को आकर्षित करने का सुनहरा अवसर मिलेगा। साथ ही किसानों को उनके उत्पादों के लिए बेहतर परिवहन और भंडारण सुविधाएँ मिलेंगी।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने भगवान श्री अंगारेश्वर महादेव की सपत्निक पूजा-अर्चना



भोपाल (नप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने रविवार सुबह उज्जैन स्थित भगवान श्री अंगारेश्वर महादेव के सपत्निक दर्शन कर पूजा अर्चना की। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने भगवान श्री अंगारेश्वर का दुग्धाभिषेक व जलाभिषेक भी किया। पूजन, जलाभिषेक कर मुख्यमंत्री डॉ यादव ने कहा कि 84 महादेव में से एक, यह मंदिर

अत्यंत प्राचीन है। पुजारी श्री मनीष उपाध्याय,श्री रोहित गुरु ने मंदिर में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूजा संपन्न कराई। पूजा के बाद मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने गौ सेवा की। इस अवसर पर जनप्रतिनिधि श्री रवि सोलंकी, श्री बहादुर सिंह बोरसुडला,श्री अभय यादव शाहिद अन्य जनप्रतिनिधि भी उपस्थित रहे।

सूदखोरों से परेशान युवक ने खाया जहर महु में बेटे के इलाज के लिए सवा लाख रुपए लिए; सुसाइड नोट में लिखा-कर्म कभी नहीं करना



मौत हो गई। रविवार को शव का पोस्टमॉर्टम किया गया। पुलिस को घटनास्थल से चार पेज का सुसाइड नोट मिला है। इसमें चार अलग-अलग लोगों से रुपए लिए जाने की बात लिखी है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच में लिया है।

चार पत्रे का पुरा सुसाइड नोट इसकी फोटो जरूर उतारना। इसकी फोटो खींचकर पुलिस को दे देना। सूदखोर परेशान करेगे, तो ये सुसाइड नोट पुलिस को दे देना। मैं वीआईपी ट्रैवल्ल्स में ड्राइवर हूँ। 22 हजार रुपए महीने सैलरी है। मैं घर में अकेला कमाने वाला हूँ। मेरे बेटे की दोनों किडनी खराब हैं। मैंने सूदखोरों से 15, 20, 10 और 5 प्रतिशत ब्याज दर पर रुपए लिए और फंस गया। मैंने बोला कि भाई- 5 प्रतिशत की दर से रुपए दे दो, तो ठीक रहेगा। मेरे घर की आर्थिक स्थिति खराब है। सूदखोर बोले- हम तुझे और रुपए नहीं दे पाएंगे।

पुलिस डायरी आने के बाद पड़ताल

महु थाना टीआई राहुल शर्मा ने बताया कि हरीश के परिजन उसे इंदौर के निजी हॉस्पिटल लेकर पहुंचे थे। यहां इलाज के दौरान मौत हो गई। मामला दर्ज होने के बाद शव को पोस्टमॉर्टम के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया। जीरो एफआईआर दर्ज कर केस डायरी महु थाने भेजी गई है। परिजन के बयानों के आधार पर जांच कर कार्रवाई की जाएगी।

सूदखोरों का नाम इस प्रकार हैं

बाबू पिता कज्जू वर्मा पता- मोहन टॉकीज के पास महु से मैंने 20 हजार रुपए 10 प्रतिशत ब्याज की दर से लिए थे। मैं ब्याज देते-देते थक चुका हूं। मैंने कहा-भाई ब्याज लेना बंद कर दे, मेरी आर्थिक स्थिति खराब है, तो वह बोला कि तेरे बेटे की तबीयत खराब है, तो मैं क्या करूं। ब्याज तो लगेगा, नहीं तो तुझे देख लेंगे।

नकुल वर्मा हाल मुकाम लालजी की बस्ती। इससे मैंने 30 हजार रुपए 15 प्रतिशत ब्याज की दर पर लिए। करीब चार साल हो गए। मूल से ज्यादा ब्याज दे चुका हूं। ब्याज नहीं लेने का बोला, तो सूदखोर ने कहा कि ब्याज नहीं लगेगा, तो तुझे जान से मार देंगे।

पप्पी से 31 हजार रुपए 20 प्रतिशत ब्याज की दर पर 2023 में लिए थे। उसने कहा था कि ब्याज तो हर महीने लगेगा। नहीं तो तेरी जान ले लूंगा।

सुरेश रानवे हाल मुकाम इंदिरा गांधी कॉलोनी से 41 हजार 500 रुपए 5 प्रतिशत ब्याज की दर पर लिए थे। उसे भी ब्याज नहीं लेने के लिए कहा, लेकिन नहीं माना।

हर तीसरे दिन करवाना पड़ता है डायलिसिस

हरीश की बहन सीमा गिरजे ने बताया कि भाई के बेटे मयूर (21) की दोनों किडनी खराब हो गई हैं। हर तीसरे दिन निजी अस्पताल में डायलिसिस करवाना पड़ता है। इस कारण बचत भी खत्म हो चुकी थी। बेटे के इलाज के लिए सूदखोरों से ज्यादा ब्याज पर पैसे लिए थे। सूदखोर लगातार फोन कर पैसे मांगते थे। एक बार जब हरीश के पास 50 हजार रुपए थे, तब सूदखोरों ने बस में जाकर मारपीट की और पैसे भी छीन लिए। घटना के बाद से हरीश ने काम छोड़ दिया था। परिवार में पत्नी के अलावा एक बेटा और एक बेटे हैं।

‘इस्लाम अरब का धर्म, भारत में सभी हिंदू थे’

आईएस नियাজ खान की सलाह- हिन्दुओं को अपना भाई माने मुसलमान

भोपाल (नप्र)। एमपी केडर के आईएसएस और पीडब्ल्यूओ विभाग में उप सचिव नियাজ खान का टवीट एक बार फिर चर्चा में हैं। नियাজ ने टवीट कर लिखा- इस्लाम तो अरब का धर्म है। यहां तो सभी हिंदू थे। हिंदू से लोग मुस्लिम बनाए गए थे। इसलिए भले ही धर्म अलग अलग हों लहू तो एक है। सभी एक संस्कृति का हिस्सा रहे हैं। अगर जो मुस्लिम अरब के लोगों को आदर्श मानते हैं वे पुनर्विचार करें। सर्वप्रथम हिंदुओं को अपना भाई माने बाद में अरब को।

एक्स बायों में लिखा मरने के लिए तैयार- आईएसएस नियাজ ने एक्स बायों में खुद को पर्यावरण प्रेमी और जलवायु परिवर्तन के लिए चिंतक बताया है। उन्होंने अपने बायों में लिखा है- ब्राउन डेजर्ट, लव डिमांड्स ब्लड, बी रेडी टू ड्राय एंड डेस्टिनी इन ड्रास (भूरा रेगिस्तान, प्यार खून मांगता है, मरने के लिए तैयार और दवाओं में किस्मत)।

नियাজ ने आज ही एक्स पर अपने एक नए नॉवेल - ' वंस आई वाज ब्लेक मेन' का कवर फोटो पोस्ट किया है। इसके कैप्शन में लिखा- इस नॉवेल में मैंने बारीकी से बताया है कि हर पैरामीटर में श्वेतों से अश्वेत क्यों पीछे हैं। अर्थविश्वास, भ्रष्टाचार, अज्ञानता, पर्यावरण प्रदूषण, अपराध, जनसंख्या वृद्धि, नकल करने में 115 अश्वेत देश एक जैसे हैं। यहां ईमानदारी की कोई कीमत नहीं होती। इनकी सभी चीजें गोरों की है।

नियोज ने आज ही एक्स पर अपने एक नए नॉवेल - ' वंस आई वाज ब्लेक मेन' का कवर फोटो पोस्ट किया है। इसके कैप्शन में लिखा- इस नॉवेल में मैंने बारीकी से बताया है कि हर पैरामीटर में श्वेतों से अश्वेत क्यों पीछे हैं। अर्थविश्वास, भ्रष्टाचार, अज्ञानता, पर्यावरण प्रदूषण, अपराध, जनसंख्या वृद्धि, नकल करने में 115 अश्वेत देश एक जैसे हैं। यहां ईमानदारी की कोई कीमत नहीं होती। इनकी सभी चीजें गोरों की है।

नेता प्रतिपक्ष ने पीएम मोदी से मिलने का टाइम मांगा

भोपाल में जीआईएस के बीच कांग्रेस विधायकों के साथ प्रधानमंत्री को बताएंगे एमपी की समस्याएं

भोपाल (नप्र)। 24 और 25 फरवरी को भोपाल में होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी बतौर मुख्य अतिथि शामिल होने भोपाल आएंगे। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने पीएम के भोपाल दौरे के दौरान कांग्रेस विधायकों के साथ मुलाकात का समय मांगा है।नेता प्रतिपक्ष ने प्रधानमंत्री के ओएसडी को लेंटर लिखकर कांग्रेस विधायकों के प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात के लिए समय देने की मांग की है। नेता प्रतिपक्ष ने ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट और मप्र की प्रमुख समस्याओं पर चर्चा के लिए टाइम मांगा है।

बीजेपी ने कहा- सिंधार को तरक्की रास नहीं आ रही- नेता प्रतिपक्ष के पत्र पर बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता डॉ.हितेश वाजपेई ने ट्वीट कर लिखा- उमंग सिंधार जी, मध्यप्रदेश की तरक्की आपको रास नहीं आ रही या फिर निवेश और विकास से जलन हो रही है? ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में व्यवधान डालकर प्रधानमंत्री जी का समय व्यर्थ करना, प्रदेश की खुशियों पर बैक लगाने की नाकाम कोशिश है।



संपादकीय

हादसों का महाकुंभ?

लगता है प्रयागराज में जारी महाकुंभ डुबकी लगाने वालो के वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ साथ हादसों का महाकुंभ भी बनता जा रहा है। ताजा हादसा नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर शनिवार रात को हुआ, जब वहां मची भगदड़ में 18 लोग बेमौत मारे गए। कई घायल हैं, जिनका इलाज चल रहा है। ये सभी प्रयागराज जाने की जल्दी में थे। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, प्रयागराज जाने वाली दो ट्रेनों के रह होने के बाद प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर मौजूद हजारों यात्री बेचैन हो गए। इस बीच एक अन्य ट्रेन वहां से निकली तो धक्का-मुक्की शुरू हो गई। इससे वहां अफरा-तफरी का माहौल बन गया। इस बीच प्लेटफार्म आने वाले श्रद्धालुओं का सिलसिला निरंतर जारी रहा। धक्का मुक्की से बचने के लिए कुछ लोगों ने तेजी से सीढ़ियां चढ़ने का प्रयास किया, लेकिन वहां से आने वाली भीड़ के चलते वह ऐसा नहीं कर सके। परिणामस्वरूप कई लोग एक दूसरे पर चढ़ गए। इस दौरान उमड़ी भीड़ का अंदाजा न तो रेलवे अधिकारी लगा पाए और न ही आरपीएफ के अधिकारी। इस पूरे मामले में प्रथम दुष्ट्या रेलवे की गलती दिखाई दे रही है। हालांकि सरकार ने हादसे की उच्चस्तरीय जांच के निर्देश दे दिए हैं। एक और जानकार सामने आ रही है, उसके मुताबिक रेलवे द्वारा अचानक गाड़ी का प्लेटफार्म बदलने से अफरा तफरी की स्थिति बनी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार प्लेटफॉर्म नंबर 12 पर शिवगंगा एक्सप्रेस जा रही थी। गाड़ी के जाते ही सारी भीड़ प्लेटफॉर्म 14- 15 पर आ गई। प्रयागराज की ज्यादातर ट्रेनें यहीं से जा रही हैं। प्लेटफॉर्म भीड़ संचालन नहीं पाया और भगदड़ मच गई। सामान्य परिस्थिति में भी अगर अचानक प्लेटफार्म बदलने की सूचना रेलवे द्वारा दी जाए तो यात्रियों के सामने मुश्किल खड़ी हो जाती है। वर्तमान में तो सभी रेलवे स्टेशनों पर कुंभ यात्रियों की भारी भीड़ है। ऐसे में रेलवे के अधिकारियों को हालात की गंभीरता को देखते हुए कोई निर्णय लेना और तदनुसार ही प्लेटफार्म बदलने की घोषणा करनी चाहिए थी, जोकि नई दिल्ली स्टेशन पर नहीं की गई। बताया जाता है कि हादसे के वक्त रेलवे पुलिस का भी कोई अंता पता नहीं था। साथ ही ट्रेन की रवानगी और प्लेटफार्म बदलने की घोषणा में यात्रियों को इतना वक्त दिया जाना चाहिए था कि वो आराम से सामान लेकर दूसरे प्लेटफार्म तक पहुंच सकें। ध्यान रहे कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर कुल 16 प्लेटफार्मर्स हैं। अगर रेलवे विशेष परिस्थिति में भी विशेष इंतजाम और सतर्कता नहीं बरत सकती और वो भी देश की राजधानी के प्रमुख रेलवे स्टेशन पर तो इतने बड़े लड़ाजमें का मतलब क्या है? शनिवार रात 11 बजे तक टीवी न्यूज चैनलों पर यह खबर आने लगी थी, लेकिन तब भी रेलवे के आला अधिकारी इसे ‘अफवाह’ बताकर खारिज करते रहे। यह रेल अधिकारियों की अस्वेददर्शीलता को उजागर करता है। विडंबना यह है कि एक तरफ सरकार महाकुंभ में हर दिन बढ़ती भीड़ के आंकड़े गर्व के साथ जारी कर रही है। इसे सही मानें तो कुंभ में हर रोज औसतन करोड़ लोग खान कर रहे हैं। दूसरी तरफ वह भगदड़ व हादसों की बात को यथा संभव दबा रही है। करीब एक माह पूर्व शुद्ध हनु कुंभ मेले में अब तक आगजनी के चार हादसे हो चुके हैं। जबकि दो बार भगदड़ हो चुकी है, जिसमे केवल 30 लोगो की मौत की पुष्टि सरकार ने की है। ताजा हादसा भले दिल्ली में हुआ हो, लेकिन उसका सम्बन्ध भी महाकुंभ से ही है। इनके हादसा कुंभ जाने और लौटने वाले श्रद्धालुओं के अलग अलग अड़क अलवा में भी दो दर्जन लोग जानें वहां चुके हैं।

विकास परियोजना

डॉ भूपेन्द्र कुमार

संस्थ लेखक

दि मोदी सरकार के बाद से भारत के रक्षा क्षेत्र में उल्लेखनीय परिवर्तन आया है, जो कि बड़े पैमाने पर आयात पर निर्भर सैन्य बल से आत्मनिर्भरता और स्वदेशी उत्पादन पर केंद्रित सैन्य बल में बदल गया है। वैश्विक स्तर पर सबसे मजबूत सैन्य शक्तियों में से एक के रूप में, भारत क्षेत्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने और रणनीतिक लक्ष्यों को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

देश का रक्षा बजट 2013-14 में 2,53,346 करोड़ से बढ़कर 2024-25 में 6,21,940.85 करोड़ हो गया है। यह देश की रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने की स्पष्ट प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इसके अलावा, मेक इन इंडिया पहल और नीति सुधारों के माध्यम से, मोदी सरकार ने घरेलू उत्पादन को सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया है और विदेशी खरीद पर निर्भरता कम की है। यह बदलाव रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करने के भारत के व्यापक दृष्टिकोण का एक प्रमुख घटक रहा है, जिसने देश को उन्नत सैन्य प्रौद्योगिकियों और उपकरणों के उत्पादन के लिए एक उभरते हुए केंद्र के रूप में स्थापित किया है। इस प्रकार मोदी सरकार की आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत भारत ने विमान निर्माण शुरू कर दिया है, लेकिन किसी भी लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर या यूसीएवी को बनाने के लिए एक बेहतरतरीन उद्यम की आवश्यकता होती है। इसके लिए भारत को दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन अब जल्द ही चीजें बदलने वाली हैं क्योंकि देश अपना स्वदेशी लड़ाकू जेट इंजन बनाने की ओर बढ़ रहा है जिसे कावेरी इंजन कहा जाता है।

कावेरी इंजन विकसित करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य लड़ाकू जेट इंजन बनाना एक चुनौतीपूर्ण काम है और इसके लिए मैकेनिकल, मेटलर्जिकल और इलेक्ट्रिकल जैसे इंजीनियरिंग क्षेत्रों में विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है। दुनिया में अब तक केवल पांच देश ही ऐसे उन्नत इंजन बना सकते हैं और वे हैं ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, रूस और चीन। भारत भी इस विशिष्ट क्लब में शामिल होने की कोशिश कर

रहा है। भारत ने सबसे पहले 1989 में कावेरी नाम से जेट इंजन बनाने की कोशिश की थी, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली। फिर 1990 के दशक में, जब भारत आर्थिक सुधारों की ओर बढ़ रहा था, परमाणु परीक्षण कर रहा था और वैश्विक स्तर पर अपनी स्थिति मजबूत कर रहा था, तब देश ने स्वदेशी सैन्य जेट इंजन बनाने की दिशा में काम करना शुरू किया, जिसका नाम भी कावेरी रखा गया।

डिफेंस एक्सपर्ट्स के अनुसार , कावेरी इंजन तेजस के लिए आवश्यक थ्रस्ट स्तर प्राप्त करने में असमर्थ था। शुरू में आपटरबर्नर के साथ 81 केएन का थ्रस्ट उत्पन्न करने के लिए डिज़ाइन किया गया, यह केवल 70-75 ब्राह्म ही प्राप्त कर सका। जो एलसीए की परिचालन आवश्यकताओं के लिए अपर्याप्त था। इसके अतिरिक्त, कावेरी इंजन शुरू में नियोजित की तुलना में भारी हो गया, जिसने तेजस विमान के समग्र प्रदर्शन और वजन-से-थ्रस्ट अनुपात को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया। कावेरी डेरिवेटिव इंजन का आदर्श वजन 1000 किलोग्राम के भीतर होना चाहिए और अगले कुछ वर्षों में उपयोग की जाने वाली सामग्रियों को बेहतर बनाने और ओवर-इंजीनियरिंग घटकों को कम करने के लिए काम चल रहा है।

कावेरी परियोजना, जिसे 53 मिलियन अमेरिकी डॉलर से वित्त पोषित किया गया था, ने कावेरी इंजन के 17 प्रोटोटाइप विकसित करने की योजना बनाई थी। हालाँकि, पहली बोली में केवल 'कबीनी' नामक मुख्य मॉड्यूल ही मिल सका। तीसरा प्रोटोटाइप पहले तीन कंप्रेसर चरणों पर परिवर्तनीय इनलेट गाइड वैन पाने वाला पहला प्रोटोटाइप था और इसका पहला रन 1995 में हुआ था।

कावेरी इंजन का पहला पूर्ण परीक्षण 1996 में हुआ था, और सभी पाँच ग्राउंड-टेस्ट प्रोटोटाइप का परीक्षण 1998 में किया गया था। प्रारंभिक उड़ान परीक्षण 1999 के लिए योजनाबद्ध थे, और तेजस पर परीक्षण 2000 में होना था। लेकिन 1998 के पोखरण परमाणु परीक्षणों के बाद लगाए गए प्रतिबंधों के कारण प्रौद्योगिकी अधिग्रहण में देरी के कारण कावेरी परियोजना धीमी हो गई। कावेरी परियोजना 2004 के मध्य

तक लगातार आगे बढ़ती रही, जब रूस में उच्च ऊंचाई वाले परीक्षण के दौरान विफलता ने तेजस लड़ाकू विमान के पहले उत्पादन बैच के साथ इसके लॉन्च की सभी उम्मीदों को समाप्त कर दिया।

सुप्रीमकॉ इंडिया के अनुसार , ड्राई कावेरी इंजन, जिसका रूस में उच्च-ऊंचाई परीक्षणों में परीक्षण गया था, भारत के पहले स्टील्थ हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) द्वारा निर्मित भारत के स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान (एलसीए) तेजस को शक्ति प्रदान करने के लिए विकसित किया गया था। हालाँकि, चूंकि इंजन आईएएफ द्वारा निर्धारित तकनीकी मापदंडों को पूरा करने में विफल रहा, इसलिए इसे 2008 में अधिकारिक तौर पर तेजस कार्यक्रम से अलग कर दिया गया।

यह ध्यान देने योग्य है कि भारत लंबे समय से अपने स्वदेशी जेट इंजन बनाने की दिशा में काम कर रहा है और कावेरी इंजन परियोजना इसी लक्ष्य का हिस्सा है। यह ध्यान देने योग्य है कि जीटीआईई ने 23 दिसंबर, 2024 को घोषणा की थी कि भारत के पहले स्टील्थ, मानव रहित लड़ाकू हवाई वाहन (यूसीएवी), घातक को शक्ति प्रदान करने के लिए विकसित नैन-आप्टरबॉर्न इंजन कावेरी को उड़ान परीक्षण के लिए मंजूरी दे दी गई है। यह भारत के स्वदेशी एयरो-इंजन विकास कार्यक्रम में एक ऐतिहासिक उपलब्धि थी। जीटीआईआई को उम्मीद है कि 2024-25 तक सभी परीक्षण पूरे हो जाएंगे और 2025-26 तक उत्पादन शुरू हो जाएंग। हालाँकि, इस परियोजना को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जिसके कारण यह तेजस की आवश्यकताओं को पूरा करने में विफल रही।

क्या प्रगति हुई है?

सुप्रीमकॉ इंडिया की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि जून 2022 में, कावेरी के उच्च-ऊंचाई वाले परीक्षणों से पहले इंजन की दहन स्थिरता को मान्य करने के लिए भारत में कई परीक्षण किए गए थे,

रूस के साथ 15 वर्षीय संधि की थी। यह भारतीय विदेश नीति का रूसी खेमे की ओर स्पष्ट झुकाव था। 1985 में भी इंदिरा गांधी की मौत के बाद जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने तब कई बार उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर चीन का दौरा किया था। और शायद यह भी इसीलिए कि तब तक अमेरिका ने चीन के साथ व्यापारिक रिश्तों के द्वार खोलने शुरू कर दिए थे। उसके बाद से भारत विदेश नीति के मामले में जिस तरह संदेव अपरिपक्व, असंतुलित और अमेरिका का पिछलग्गू रहा है, वही उसका कारण था। इसी दौर में चीन और अमेरिका के व्यापारिक रिश्ते बड़ी दूर तक परवान चढ़े। इसका एक परिणाम



यह हुआ कि चीनी माल से अमेरिका का बाजार भर गया और मानसिक रूप से तथा अधोषित रूप से अमेरिका को अगुवा मानने वाले भारत जैसे देश ने चीन के साथ व्यापारिक रिश्तों के नाम से रिश्ते बनाना शुरू कर दिये। चीन के लिए दुनिया का बहुत बड़ा बाजार मिल गया और चीन ने रबाजार समाजवाद के नाम से पूंजीवाद का रास्ता अपना लिया। चीन ने साम्यवादीय विचारों को त्याग दिया। साम्राज्यवादी तो वह पहले ही था, अब पूंजीवादी भी बन गया। निजी संपत्ति के ऊपर लगाए गए सभी प्रतिबंध हटा दिए गए और चीनी उद्योगपति, पूंजीवादी दुनिया और अमेरिका के पूंजीपतियों के बराबर खड़े हो गए।

लगभग तीन दशक अमेरिका और चीन के व्यापारिक रिश्ते चलते रहे, परंतु इसका दूसरा परिणाम यह हुआ कि पूंजी में अग्रणी देश बनने के बाद चीन की सुप्त महत्वाकांक्षाएं पुनरु जागृत हो गईं। चीन ने आगामी सदी के लक्ष्यों को ध्यान में रखकर श्वन बेल्ट वन रोड्‍य के नाम से ऐसी महत्वाकांक्षी योजना का काम शुरू किया जो उसे सड़क मार्ग से यूरोप और ईरान तक जोड़ दे तथा दुनिया के बाजार का नियंत्रण उसके हाथ आ जाए। इसके लिए चीन ने दो महत्वापूर्ण लक्ष्य साधे, एक- चीन में साम्यवादी तानाशाही के चलते मजदूरों के अधिकार लगभग नहीं है, श्रम सस्ता है और इसीलिए चीनी माल पूंजीवादी देशों या मिश्रित अर्थव्यवस्था वाले अन्य देशों की तुलना में बहुत सस्ता है। यह दुनिया के उपभोक्ताओं के

लिए एक स्वाभाविक आकर्षण है। दूसरे- अमेरिकी अर्थव्यवस्था की कमजोरी के चलते जो साहूकारी साम्राज्यवाद शुरू हुआ था वह अमेरिका के हाथों से फिसलने लगा और चीन ने उन साहूकारी साम्राज्यवादी ठिकानों को अपनी साहूकारी साम्राज्यवाद के प्रभाव और नियंत्रण में लेना शुरू कर दिया। यह एक प्रकार से दुनिया में अमेरिकी प्रभाव को कम करने वाला और रंगीन दुनिया के बड़े इलाकों में चीनी पूंजी को स्थापित करने वाला था। म्यांमार, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान तक इसी साहूकार वाद साम्राज्यवाद ने चीनी प्रभाव का



विस्तार किया। अमेरिका के दबाव या प्रभाव में 1991 में नरसिंह राव के प्रधानमंत्रित्व काल में विश्व बैंक में रह चुके वित्तमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने एकतरफ 1 जनवरी 1995 को दुनिया के पूंजीवादी देशों के साहूकारी दस्तावेज के स्वरूप वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन (डब्ल्यूटीओ) के समझौते पर हस्ताक्षर किए और दूसरी तरफ भारत की विदेश नीति जो दक्षिण एशिया संगठन या (सार्क) केन्द्रित थी को बदलकर रशुक दू दि ईस्ट्‍य के नाम पर नई विदेश नीति की शुरुआत की। परिणामस्वरूप भारत ने पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान और सार्क के देशों पर ध्यान देना कम कर चीन की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाना शुरू कर दिया। भारत के उद्योग और व्यापार के नेताओं, सरकारी प्रचार वंत्र ने जोर-शोर से प्रचार करना शुरू किया कि अब दुनिया में विदेश नीति का आधार और निर्णायक पक्ष व्यापार ही होगा। यह सब चीन के साथ दोस्ती करने के लिए छिपे तर्क थे, जो देश के आम आदमी के रझान को बनाते हैं, परंतु भारत और चीन की यह व्यापारिक यारी बहुत दिन तक नहीं चल पाई।

चीन स्थित डोकलाम घाटी के भारतीय भू-भाग में चीन ने अपनी सेना का प्रवेश करा दिया तथा गलवान घाटी में तो भारतीय सैनिकों और अधिकारियों को मार-मार कर पीछे किया गया। डोकलाम में जब इस चीनी अतिक्रमण की चर्चा आई तो देश के रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने स्वीकार

किया कि चीनी सेना ने भारतीय सीमा पर अतिक्रमण किया है। तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रक्षामंत्री का खंडन करते हुए कहा श्भारत की सीमा में न कोई घुसा है... न ही किसी ने अतिक्रमण किया है, परंतु अब पिछले दिनों और पिछले कुछ वर्षों में पहले स्तर पर भारत और चीन के सन्य अधिकारियों के बीच लंबी चर्चा का दौर चला, फिर भारत और चीन के विदेश मंत्रियों के बीच विमर्श का दौर चला और अभी कुछदिनों पूर्व भारत सरकार की यह वक्ताि आई कि चीन और भारत की सेना पीछे हटेंगी और यह प्रक्रिया शुरू हुई। प्रधानमंत्री मोदी से जनता जानना चाहती है कि जब कोई हमारी सीमा में घुसा ही नहीं था तो चीनी सेना कहाँ से पीछे हटेगी? दरअसल यह प्रधानमंत्री के झूठ का पर्दाफ़श है, और भारतीय सीमाओं के साथ किया गया खिलवाड़ है, जो विश्वासघात से कम नहीं है। भारत सरकार को बताना होगा और बताना चाहिए कि क्या चीन के साथ मंत्री स्तर की वार्ता में 1962 में चीन द्वारा कब्जाई गई भारतीय भूमि, तिब्बत की आजादी-अंग्रेजों के द्वारा खींची गई मैकमोहन लाइन तथा डॉ. लोहिया द्वारा बताई गई भारतीय सीमा, जो मैकमोहन लाइन के भी काफ़ी आगे तक है, पर क्या चर्चा हुई।

क्या भारत ने अपनी उन पुरानी सीमाओं को चीन से दोस्ती के नाम पर समर्पित कर दिया है? क्या भारतीय विदेश मंत्री केवल श्रेहरा बचाओय विदेश नीति पर चल रहे हैं? क्या तथ्यों को छुपाकर देश को गुमराह करना चाहते हैं? दुनिया में फिर नया शक्ति समीकरण बन रहा है। अमेरिका, रूस, ईरान आदि की एकजुटता के खिलाफ फिर चीन को साधना चाहता है, और अमेरिकी सत्ताधीशों ने रूस बदला है और भारत के पिछलग्गू सत्ताधीशों को उस रास्ते पर चलने के लिए बहाना चाहिए। कल तक भारत चीनी ऐप, चीनी माल पर रोक की बात करता था। अब नई यारी के बाद सुर बदल जाएंगे और शायद फिर से हिन्दी चीनी भाई-भाई के नारे सुनने को मिलेंगे। बाजार की प्रचार की शक्तियां चिख़-चिख़ाकर प्रचार करेंगी कि दुनिया को युद्ध से बचाने के लिए रूस, ईरान, पाकिस्तान की बन रही धुरी को तोड़ना है इसलिए चीन से दोस्ती जरूरी है, ताकि चीन और रूस के बीच संबंध ख़ासि़त हो सकें और अमेरिका तथा चीन की सुविधा के लिए भारत और चीन की दोस्ती जरूरी है।

मैं अंत में कहूँगा कि भारत चीन से दोस्ती करे, यह महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि महत्वपूर्ण यह है कि भारतीय सीमाओं की रक्षा और चीन द्वारा कब्जाई गई भारतीय भूमि की वापसी, तिब्बत की आजादी। क्या प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि भारत-चीन के बीच विवाद का मूल कारण भारतीय जमीन की वापसी के लिए चीन सहमत है? क्या हिमालय की हजारों किलोमीटर जमीन, जो 1962 में चीन ने बलपूर्वक छीनी थी, को वह वापस कर रहा है? क्या चीन अरूणाचल को भारतीय भू-भाग मान रहा है? और क्या अपने नक्शों को संशोधित करता है? अगर नहीं तो फिर चीन से यारी अल्पकालिक और धोखा ही साबित होगा।

भगदड़ से मौन जिंदगियां

कटाक्ष

सूर्यदीप कुशवाहा

लेखक संस्थाकार हैं।

महाकुंभ का तिलिस्म अब भी टूटा नहीं है। यह जाड़ू तिलिस्म है। फसस्वरूप नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर उमड़ी भीड़ में भगदड़ और घटी दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना। असमय काल के गाल में समा गई जिंदगियां। हर हादसों में प्रशासन पहले अफवाह बताता है फिर सुबूत को मिटाने की नाकाम कोशिश करता है। सोशल मीडिया में हाहवाक मचता है। हादसों की चीख-पुकार का वीडियो आ ही जाता है। सच तो सच है। सच कहाँ दबता है? प्रशासन अपनी घोर लापरवाही को मानता नहीं है। इसको पहले छिपाना चाहता है। लेकिन उच्चस्तरीय जाँच का आदेश देता है। हालाँकि यह जाँच की उच्चता के पैमाना पर खरा नहीं उतरता। आजकल खरा सोना भी कहाँ मिलता है। शासन को बस अपने आसन की चिंता होती है। जनता की चिंता में दुबला होना नहीं चाहता है। बड़ी विडंबना है और यह महाकुंभ में बना है।

आमजन को सुविधाएँ हैं लेकिन दुस्वारियाँ अंतहीन है।यह रेलवे स्टेशन से लेकर बस अड्डों तक ही नहीं सिमटी हैं बल्कि ऑटो, कार कई जिलों और राज्यों में जाकर का झाम है। शव के रहने वाले आमजन परेशान हैं लेकिन शान है। शासन व जनता कब चेतेंगी? हादसे से सबक नहीं लेती हैं। अब इस्तीफा भी जिम्मेदार नहीं देते। बेरामी से वक्तय बचान देते हैं और फिर मीडिया में रो लेते हैं। जनता अनाड़ी है और ये बनावटी संवेदना के खिलाडी हैं।कब तक हादसों को निमंत्रण देते रहेंगे और प्रशासन कब नियंत्रण करेगा। भगदड़ की त्रासदी से रेलवे प्रशासन के इंतजामों को लेकर सवाल उठ गए। भीड़ प्रबंधन की जटिल चुनौतियाँ हवाी हो गईं। आस्था के समुद्र में भक्तों की विशाल संख्या सुसंगत प्रबंधन की मांग करती है। लेकिन आत्मन यह है कि रेलवे प्रशासन पहले छुपाने के आरोप लगे। बताया गया कि भगदड़ कोरा अफवाह है।, लेकिन खबरें दब नहीं सकती। अब तक मरने वालों की संख्या 18 बता सकी है। दूसरी तरफ,



व्यवहार को समझना भगदड़ रोकने का अहम पहलू है। शोध से पता चला है कि भीड़ के व्यवहार को समझने से बल आधारित नियंत्रण के बजाय भीड़ नियंत्रण के लिए समुदाय आधारित दृष्टिकोण को बढ़ावा मिला है। अहम सुझाव यह है कि प्रवेश के लिए अनिवार्य पंजीकरण व्यवस्था का होना जरूरी है।

रेलवे प्रशासन को दायित्व बोध हो जिससे हादसे ना हों। यह दुर्घटना छेटी जरूर है लेकिन इसके संदेश बड़े हैं। अगर प्रशासन चेत जाए तो ठीक है। वरना भगदड़ से से जीवन ऐसे ही समाप्त होगा। हमें सही गलत समझना होगा। जिससे अंधी भीड़ का हिस्सा बनने से बचा जा सके। अपनी और अपने परिवार की जान की परवाह करना तर्क संगत है। वरना आप जानते हैं कि हादसों से प्रशासन की गलबहियां, भगदड़ से मौन जिंदगियां...।

स्वामी, सुबह सवेरे मीडिया एल.एल.पी. के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक उमेश त्रिवेदी द्वारा श्री सिद्धिविनायक प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 26-वी, देशबंधु परिसर, प्रेस कॉम्पलेक्स, जेन-1, एम.पी.नगर, भोपाल, म.प्र. से मुद्रित एवं डी-100/46, शिवाजी नगर भोपाल से प्रकाशित।

प्रधान संपादक

उमेश त्रिवेदी

कार्यकारी प्रधान संपादक

अजय बोकिल

संपादक (मध्यप्रदेश)

विनोद तिवारी

वरिष्ठ संपादक

पंकज शुक्ला

प्रबंध संपादक

अरुण पटेल

(सभी विचारों का न्याय क्षेत्र भोपाल रहेगा)

RNI No. MP/PHIN/ 2003/ 10923,

Ph. No. 0755-2422692, 4059111

Email- subahsaverenews@gmail.com

'सुबह सवेरे' में प्रकाशित विचार लेखकों के निजी मत हैं।

इनसे समाचार पत्र का सहमत होना आवश्यक नहीं है।

व्यंग्य

डॉ. प्रेमचंद द्वितीय

लेखक व्यंग्यकार हैं।

मानिग वॉक के दौरान साहित्यिक रूझान वाले पं शिवनारायण को कालोनी के बगीचे में घूमते घूमते गुलाब पर नजर पड़ गई। गुलाब की महक और कांटों को देखकर उन्हें वेलेंटाइन वीक का रोज़ दे याद आ गया और वे गुलाब की महक और कांटों में उनका साहित्यिक आईना देखने लगे, गुलाब के रंग को देखकर रोमांचित हो गए और बोले, वैसे तो वेलेंटाइन वीक को सिर्फ कपल और प्रेमी ही सोलिब्रेट करते हैं। लेकिन हम जैसे साहित्यिक लोग की रोमान्टिक रचना नहीं हो तो वेलेन्टाइन टाईड्र्टाई फिश हो जाए। इसी कारण वैंलेंटाईन डे से कोई नए रोमांटिक संदर्भ चुनकर वेलेंटाइन के आठवें डे को साहित्यिक डे में तब्दील कर दिया जाए।

यह कह कर वे साहित्य वेलेंटाइन डे पर बोलने लगे। उनका बोलना था कि कॉलोनी के अन्य कवि लेखक और

छोटे मोटे रचनाकार भी आ गए । जिससे धीरे धीरे भीड़ का मजमा इकट्ठा हो गया ।साहित्यिक वेलेंटाइन की बानगी प्रस्तुत कर पंडित जी ने मसमने को मजे लाने का प्रयास किया। वेलेंटाइन के पहले दिन पर वे बोले वेलेन्टाइन साहित्य का रोज़ डे रोमांटिक रुचि वाले शाश्वत प्रेम के साहित्य को बुनकर उसकी महक फैलाते हैं । वे बोले रोमियो जुलियट में गुलाब प्रेम का रूपक है ।जिस तरह सियासत में कमल राजा हो गया है। उसी तरह साहित्य में गुलाब राजा है ।गुलाबी रंग से साहित्य का रंग जमता है ।साहित्य में कांटो के गुलाब है तो गुलाबी रंग में साहित्य की कर्मिड़ी ,कला ,रोमांस ,रोमांच ,दोस्ती,आलोचना ,कई रूपक ,गड़बड़ी जैसे अनेक रहस्य छिपे हैं । शेक्सपियर के वृहत लेखन में वेलेंटाइन के अनेक संदर्भ शामिल है ।साहित्य में आलोचक के पास , रोज़, की खुशबू कम , कांटे ज्यादा होते हैं। साहित्य और लेखन में मिजाज पुरसी और तरफदारी भी वेलेंटाइन के किस्म किस्म के डे मनवाते हैं ।

इस पर सुनील भैया बोले वेलेंटाइन का प्रपोज डे साहित्य में च्यार के इजहार और दिल से दिल को समझने की कविता

वैलेंटाइन का आठवां दिन साहित्य डे!

,शायरी और लेख लिखवाता है । लव लेटर से लेकर ग्रींटिंग के प्रपोजल प्रेगला भी प्रपोज डे से मिलती हैं । पंडित जी वेलेंटाइन चकालेट डे को साहित्यिक वेलेन्टाइन रेवडी डे के रूप मे मनाने के लिए बोले । वेलेंटाइन डे में चाकलेट खिलाने से प्रेम उमड़ता है। लेकिन साहित्यिक वेलेन्टाइन डे में बगैर पारिश्रमिक लिए उलटे कुछ ले दे कर ,किसी से लिखवाकर साहित्यिक रेवडी बांटेने से यह डे साहित्य का , रेवडी डे ,मनना चाहिए ।

वेलेंटाइन के , टेडी डे , को बड़े उत्साह से मनाने का जोर देते हुए पंडित जी बोले चुकि हर महीने, हर हफ्ते लेखक ,कवि के यहां अस्वीकृति के मेल और लेटर आते है जिससे लेखक तिरछ बांका हो जाता है ,संपादक को कोसता है ,लेकिन , टेडी डे, गर्म जोशी से संपादक से सहज बनने का रास्ता दिखाता है ।वेलेंटाइन का डे साहित्य का प्रामिस डे भी होता है ।साहित्य में सबसे ज्यादा महत्ता है प्रामिस की हैं । प्रामिस की इकरार बाजी सम्पादक लेखक के बीच चलती है । छपने छपने के इतने प्रामिस करते है कि प्रामिस ही मिस हो जाता है । वेलेंटाइन का

,हग डे ,साहित्य मे आलिंगन को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है इस साहित्यिक हग डे में लेखक बुद्धिजीवी एक दूसरे से गले तो मिलते है। लेकिन एक दूसरे को गले पड़ जाता है। साहित्यिक हग डे मे गले पड़कर गिले गिले कब गीले गीले हो जाए पता ही नही चलता है। वेलेंटाइन का ,किस डे , कपल तो , किस, कर लेते हैं । लेकिन साहित्य में ,किस डे , का मतलब किस उपन्यासकार ,व्यंग्य कार ,कहानीकार ,कवि ,आलोचक ,समालोचक किस को होतें,जुबान से तारीफ के पुल बांध कर उस डे की सार्थकता प्रदान करते है

पंडित जी बोले साहित्यिक वेलेंटाइन में किस किस को कैसे दूढ़े और किसको प्रपोज करे, किसको प्रामिस करे, किसको गले लगाकर हग करें , किसे सियासी रेवडी की तरह पुरस्कार ,अलंकरण ,पदवी , बांटे और साहित्य सम्मान का दुपुद्ग बांधे ।इस तरह वेलेंटाइन का साहित्य में योगदान शेक्सपियर से लेकर मुझ जैसे लेखक तक में अपना वजूद कायम किए हुए है इसीलिए वैंलेंटाइन का आठवां डे ,साहित्य डे , के रूप में मनाया जाए!

कानून और न्याय

विनय झैलावत

(लेखक पूर्व असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल एवं वरिष्ठ अधिवक्ता हैं)



अनुकंपा नियुक्ति के मामले में उचित समय क्या होगा ? यह काफी हद तक विचाराधीन अनुकंपा नियुक्ति के लिए नीति/योजना पर निर्भर करता है। यदि आवेदन करने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित की गई है और दावेदार उस अवधि के भीतर आवेदन करता है, तो समय के अंतराल को अस्वीकृति का आधार नहीं माना जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने समक्ष अनुकंपा नियुक्ति के एक मामले में हाल ही में कहा कि प्रत्यर्थी के पिता की मृत्यु दिसंबर 2001 में हुई थी। लेकिन, कर्मचारी परिवार के सदस्य को देरी के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता। क्योंकि, वह विभाग के समक्ष और उसके बाद उच्च न्यायालय के समक्ष अपने दावे के संबंध में निरंतर कार्यवाही कर रहा था। इसलिए, इस बात की परवाह किए बिना कि आवेदक की वर्तमान आयु कितनी है, उसकी आयु उसके दावे को आगे बढ़ाने और गुण-दोष के आधार पर उस पर विचार करने से रोकने के लिए निर्धारक नहीं हो सकती है। यह पता लगाने के लिए वित्तीय स्थिति की जांच करना कि क्या कमाने वाले कर्मचारी की मृत्यु के कारण प्रतिवादी और उसकी माँ पूरी तरह से वित्तीय संकट में रह गए थे।

न्यायालय ने यह भी मत व्यक्त किया कि कोई भी आश्रित, जो अन्यथा उपयुक्तता सहित अनुकंपा नियुक्ति के लिए सभी मानदंडों को पूरा करता है, को केवल आयु-सीमा के आधार पर उनकी अनुकंपा नियुक्ति के आवेदन को निरस्त नहीं किया जाना चाहिए। यदि दावेदार की आयु छूट योग्य सीमा के भीतर पाई जाती है, तो विवेकाधिकार उपयुक्त मामले में प्रयोग करने के लिए उपलब्ध है और इसका उपयोग किया जाना चाहिए। आयु में छूट पूरी प्रक्रिया के अंतिम चरणों में उठाया जाने वाला एक विवेकाधिकार कदम है। लेकिन, नियुक्ति के लिए अन्य सभी शर्तों को पूरा किया जाना भी जरूरी है। यदि इस तरह के किसी मामले में, कि मृतक का परिवार गरीबी रेखा के अंदर नहीं पाया जाता है, तो पहली सीमा को ही पार नहीं किया जा सकता है। इस तरह, प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ेगी। ऐसे मामले में, आयु में छूट पर विचार करना

जरूरतमंदों के लिए अनुकंपा नियुक्ति पर विचार जरूरी

अनुकंपा नियुक्ति की मृतक कर्मचारी के परिवार में अत्यंत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। इन नियुक्तियों का आधार और औचित्य, संकटग्रस्त तथा अभावग्रस्त परिवारों को अनुतोष प्रदान करना होता है। इसलिये इन नीतियों का उद्देश्य परिवार को तत्काल सहायता प्रदान करना होता है। यह ध्यान देने योग्य बात है कि ऐसा अधिकार सेवा के दौरान मरने वाले कर्मचारी की सेवा की शर्तों में नहीं है, जिसे किसी भी प्रकार की जांच या चयन प्रक्रिया के बिना आश्रित को दिया जाना चाहिये।

निष्क्रिय औपचारिकता होगी।

इसके अलावा, न्यायालय ने स्पष्ट किया कि अपीलीय न्यायालय की शक्ति कानूनों द्वारा सीमित है। तदनुसार सर्वोच्च न्यायालय ने अपील को आंशिक रूप से स्वीकार किया एवं विवादित निर्णय को अस्वीकार कर राशि का एकमुश्त भुगतान करने का निर्देश दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने अनुकंपा नियुक्ति से संबंधित इस मामले की अपील पर निर्णय लेते हुए कहा कि यह देखा जाना चाहिए कि कोई योजना मृत्यु के समय प्रभावी है अथवा नहीं। इस प्रकरण में प्रत्यर्थी के पिता केनरा बैंक में काम कर रहे थे। उनकी सेवानिवृत्ति से पहले वर्ष 2001 में उनका निधन हो गया। तदनुसार, कर्मचारी के परिवार के सदस्य ने 1993 की योजना के तहत अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति मांगी। हालांकि, उच्च न्यायालय के समक्ष इस मुकदमे के लंबित रहने के दौरान, एक और योजना (2005) शुरू की गई थी। इसमें मृतक कर्मचारियों के परिवार के सदस्य एकमुश्त अनुग्रह राशि के भुगतान के हकदार थे। विशेष रूप से, बैंक ने 1993 की योजना के तहत नियुक्तियों को बंद करते हुए एक परिपत्र जारी किया था।

इस पृष्ठभूमि में, न्यायमूर्ति दीपाकर दत्ता और न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने परस्पर विरोधी न्यायिक राय के बारे में टिप्पणी की। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि केनरा बैंक बनाम एम.महेश कुमार के मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि अनुकंपा नियुक्ति के दावे का निर्णय दावे के बाद शुरू की गई योजना के आधार पर नहीं किया जा सकता है। इन मामलों में न्यायालय के अलग-अलग विचार थे। अभिषेक कुमार बनाम हरियाणा राज्य, मामले में न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया कि चूंकि 2003 के नियम ऐसे समय में अस्तित्व में नहीं थे जब अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति का दावा किया गया था। इसलिए इसे 2001 के नियमों के अनुसार माना जाएगा।

केनरा बैंक के फैसले में भी ऐसा ही दृष्टिकोण



अपनाया गया था। इसके विपरीत, एसबीआई. बनाम राज कुमार, जीबी ग्रामीण बैंक बनाम चक्रवर्ती सिंह मामलों में न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया कि फैसले के समय केवल नई योजनाएं लागू होंगी। पूर्व योजना के अधीन मामले पर विचार करने का न्यायालय में कोई निहित अधिकार नहीं है। शीओ शंकर तिवारी बनाम कर्नाटक राज्य कहा गया कि इस तरह के दावे पर विचार करते समय, आवेदन पर विचार करने की तारीख पर प्रचलित मानदंड ही लागू होंगे। पीठ ने कहा, उपरोक्त उद्धृत निर्णयों से ली गई अनुकंपा नियुक्ति को नियंत्रित करने वाले कानून को लागू करते हुए, हमारी राय यह है कि आवेदन पर विचार करने की तारीख पर प्रचलित मानदंड अनुकंपा नियुक्ति के दावे पर विचार करने का आधार होना चाहिए। एक कर्मचारी का आश्रित, सरकारी कर्मचारी की मृत्यु पर



अर्जित किसी भी निहित अधिकार के अभाव में, केवल उसके आवेदन पर विचार करने की मांग कर सकता है। अनुकंपा नियुक्ति की मृतक कर्मचारी के परिवार में अत्यंत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। इन नियुक्तियों का आधार और औचित्य, संकटग्रस्त तथा अभावग्रस्त परिवारों को अनुतोष प्रदान करना होता है। इसलिये इन नीतियों का उद्देश्य परिवार को तत्काल सहायता प्रदान करना होता है। यह ध्यान देने योग्य बात है कि ऐसा अधिकार सेवा के दौरान मरने वाले कर्मचारी की सेवा की शर्तों में नहीं है, जिसे किसी भी प्रकार की जांच या चयन प्रक्रिया के बिना आश्रित को दिया जाना चाहिये। इसलिये, अनुकंपा नियुक्ति, अत्यधिक वित्तीय कठिनाई का सामना कर रहे मृतक कर्मचारी के परिवार को अनुतोष देने के लिये प्रदान की जाती है। क्योंकि रोजगार के बिना, परिवार

वित्तीय एवं अन्य संकट का सामना करने में सक्षम नहीं हो सकता है। उक्त नियुक्ति किसी भी मामले में दावेदार द्वारा ऐसी अनुकंपा नियुक्ति के लिये निर्धारित नीति, निर्देश या नियम आवश्यकताओं को पूरा करने के अधीन होगा। अनुकंपा नियुक्ति के मामलों में उल्लेखनीय फैसलों में विमला श्रीवास्तव बनाम उत्तर प्रदेश एवं अन्य का जिक्र कर सकते हैं। इस मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1974 के नियम में अविवाहित आश्रय प्राप्त पुत्री शब्द को संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 का उल्लंघन मानते हुए रद्द कर दिया था। साथ ही उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य बनाम माधवी मिश्रा एवं अन्य मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा कि विवाहित पुत्री अधिकार के रूप में अनुकंपा नियुक्ति का दावा नहीं कर सकती है। एक अन्य मामले में कर्नाटक में कोषागार निदेशक एवं अन्य बनाम वी. सौम्यश्री में उच्चतम न्यायालय ने अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति प्रदान करने के सिद्धांत को संक्षेप में कहा कि अनुकंपा नियुक्ति सामान्य नियम का अपवाद है। साथ ही किसी भी अभ्यर्थी को अनुकंपा नियुक्ति का अधिकार नहीं होता है। राज्य की सेवा में किसी भी सार्वजनिक पद पर नियुक्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के अनुसार सिद्धांत के आधार पर की जानी चाहिए। अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति केवल राज्य की नीति द्वारा निर्धारित मानदंडों को पूरा करने और/या नीति के अनुसार पात्रता मानदंडों की संतुष्टि पर की जा सकती है। आवेदन पर विचार की तिथि को प्रचलित मानदंड अनुकंपा नियुक्ति के दावे पर विचार करने के आधार होना चाहिए। एक अन्य मामले में महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य बनाम सुश्री माधुरी मारुति विधाते मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि, मृतक कर्मचारी की विवाहित पुत्री को उसकी मृतक मां पर आश्रित नहीं माना जा सकता है। विशेषकर तब जब कर्मचारी की मृत्यु को काफी समय बीत चुका हो।

इंडिया,ज गॉट लेटेंट- दूसरा पहलू

अनुष्का

(लेखिका पीआर एंड सोशल मीडिया एक्सपर्ट व मीडिया विस्‍ट्रो ऑफिशियल की फाउंडर हैं)

सभ्यता ये शब्द मैंने पहली बार अपनी इतिहास की किताबों में पढ़ा-सुना और समझा था। सभ्यता शब्द को मानव समाज के एक सकारात्मक, प्रगतिशील और समावेशी विकास को इंगित करने के लिये किया जाता है।

हाल ही में आजकल एक युवाओं द्वारा पसंद किए जाने वाला शो Indias Got Latent चर्चा में है आप यह सोच रहे होंगे की मैंने सभ्यता की बात करते करते इस शो की चर्चा बीच में क्यों उठाई तो इसीलिए क्योंकि इसी वजह से ये शब्द सभ्यता फिर से चर्चा में आया है । अगर आप Indias got latent से संबंधित खबरों को देख या सुन रहे है तो जानते ही होंगे कि उस शो में बैठे कुछ panelists के कई बयान और स्वयं के रक्षण में दिए गए प्रतिउत्तर, valentines day के दिन जन्म लेने वाले कथित ‘सभ्य समाज के संदेश वाहक’ को आपत्ति जनक लग रहे हैं। आपको बता दे कि जब भी समाज में बलात्कार, छेड़ छाड़, अत्याचार आदि के मामले आते है तो यही ‘सभ्यता के संदेश वाहक’ उस समय पर गायब नज़र आते हैं ।

कॉमेडी या प्रहसन हमें थोड़ी देर के लिए असलियत में चल रही प्रेरानामियों से दूर ले जाने के लिए होता है। इसमें सभी कुछ कार्पनीक होता है और इसका असलियत से दूर दूर तक वास्ता ना के बराबर ही होता

गालियों से सभ्यता कैसे क्षतिग्रस्त हो जाएगी?

हाल ही में आजकल एक युवाओं द्वारा पसंद किए जाने वाला शो India s Got Latent चर्चा में है आप यह सोच रहे होंगे की मैंने सभ्यता की बात करते करते इस शो की चर्चा बीच में क्यों उठाई तो इसीलिए क्योंकि इसी वजह से ये शब्द सभ्यता फिर से चर्चा में आया है । अगर आप Indias got latent से संबंधित खबरों को देख या सुन रहे है तो जानते ही होंगे कि उस शो में बैठे कुछ panelists के कई बयान और स्वयं के रक्षण में दिए गए प्रतिउत्तर, valentines day के दिन जन्म लेने वाले कथित ‘सभ्य समाज के संदेश वाहक’ को आपत्ति जनक लग रहे हैं। आपको बता दे कि जब भी समाज में बलात्कार, छेड़ छाड़, अत्याचार आदि के मामले आते है तो यही ‘सभ्यता के संदेश वाहक’ उस समय पर गायब नज़र आते हैं ।



है । कॉमेडी के अपने अपने रंगरूप होते हैं, जिन्हे पहले के लोग और आज के युवा अपने अपने समय के हिसाब से देखते हैं और अपना मनोरंजन करते है । Indias got latent भी एक ऐसा ही शो था, जिसमे सिर्फ

मज़ाक बनाना है, जिन्हे चर्चा में लाना सामाजिक शैली को भंग करना है। यानी जो सामाजिक तौर पे चर्चा में नहीं लाए जा सकते। पर क्या Dark कॉमेडी करने से या कॉमेडी करते करते गाली गलौज करने से हमारी भारतीय +सभ्यता+ क्षतिग्रस्त हो जाएगी?

हालांकि मैं यह ज़रूर इंगित करना चाहूँगी कि ऐसे कार्यक्रम अच्छी मानसिकता को बढ़ावा नहीं देते, पर इनके आने से पूर्व भी तो समाज में असामाजिक और जघन्य अपराध और मानसिकताएं मौजूद थीं। अगर व्यावसायिक दृष्टिकोण से देखें तो youtube जैसे प्लैटफॉर्म पर क्रिएटरनुमा दुकानदार सिर्फ अपना सामान बेच रहे हैं यह जिम्मेदारी और इच्छा आपकी है की आपको इसे खरीदना है या नहीं !

और भले ही ये सभ्यता के कथित संदेश वाहक जितने भी संस्कारी बन लें, कहीं ना कहीं ऐसे कार्यक्रमों को छुट्टा कर देखने से ये भी पीछे नहीं हटते। और यह

बात किसी से छुपी नहीं है की इस social media के ज़माने में हर किसी को "footage" चाहिए वो ये क्रिएटर हैं या ये सभ्य समाज के कथित संदेश वाहक। देखिए बात अगर सभ्यता की ही है तो आप किस सभ्य समाज की बात करते हैं ? कहाँ गया वो सभ्य समाज जब एक पत्नी पे हाथ उठा रहा था उसका पति, कहाँ वो सभ्य समाज जब हाथरस में वो दलित लड़की बलात्कार जैसे जगन्य अपराध की शिकार हुई, कहाँ था वो सभ्य समाज जब निर्भया जीवन और मृत्यु के बीच जंग लड़ रही थी, कहाँ था वो सभ्य समाज, जब मौमिता अपनी जान बख़शने के लिए चीख पुकार लगा रही थी ? बात यहाँ सभ्य-असभ्य की नहीं है। बात यहाँ पर उन तमाम मुद्दों पर करने की है, जिसपर सब खामोश है। और इस खामोशी का आलम देखिए हाल ही में मिस्बाह नाम की एक छोटी बच्ची का बलात्कार हुआ और कोई उसपे बात नहीं करना चाहता ।

विरासत से साक्षात्कार

वीरेंद्र व्यास

लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं।



वर्तमान में जो लोग 70-75 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं और जो तत्कालीन मध्य भारत या मध्य प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा प्राप्त कर रहे थे वे निश्चित रूप से खैरागढ़ संगीत विश्वविद्यालय का नाम जानते होंगे। उन दिनों पुस्तकों में खैरागढ़ संगीत विश्वविद्यालय का उल्लेख मिलता। मेरे भी विद्यार्थी जीवन से ही खैरागढ़ के प्रसिद्ध संगीत विश्वविद्यालय को देखने की इच्छा ने जन्म ले लिया था।

फरवरी 2025 मे जब छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर जाने का प्रसंग आया तो बीच में खैरागढ़ नगर भी आया और खैरागढ़ मे संगीत विश्वविद्यालय होने की स्मृति भी ताजा हो गई। इच्छा हुई कि संगीत विश्वविद्यालय का रुख किया जाए। जब मैं विश्वविद्यालय परिसर पहुंचा तो वहां के सिक्थोरिटी गार्ड ने बताया कि वर्तमान में विश्वविद्यालय के डीन डॉ. योगेंद्र चौबे हैं। विश्वविद्यालय के डीन डॉ. योगेंद्र चौबे थिएटर फैकल्टी के हैड हैं। वे शहर से बाहर थे तो उनसे दूरभाष पर बात ही हो पाई। यह मेरे लिए सुखद था कि डॉ चौबे ने मेरे ऑडिटोरियम परिसर पहुंचने के पहले ही उन प्रोफेसर प्रशासन को मेरे आने की जानकारी दे दी थी। प्रोफेसर प्रशासन प्रशांत मलतियार ने विश्वविद्यालय के बारे में तमाम जानकारी देने के उपरांत बताया कि उस वक?त वहां भारत रंग महोत्सव आयोजित हो रहा है। सभी जानते हैं कि विश्वविद्यालय में कई दशकों से संगीत की विभिन्न विधाओं में शिक्षा दी जाती है। अतीत के बारे में जानकारी लेने पर पता चला कि खैरागढ़ क्षेत्र पहले रियासत हुआ करता था। वहां के तत्कालीन राजा

खैरागढ़- हर ओर संगीत स्वर लहरियों का आस्वाद

फरवरी 2025 में जब छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर जाने का प्रसंग आया तो बीच में खैरागढ़ नगर भी आया और खैरागढ़ मे संगीत विश्वविद्यालय होने की स्मृति भी ताजा हो गई। इच्छा हुई कि संगीत विश्वविद्यालय का रुख किया जाए। जब मैं विश्वविद्यालय परिसर पहुंचा तो वहां के सिक्थोरिटी गार्ड ने बताया कि वर्तमान में विश्वविद्यालय के डीन डॉ. योगेंद्र चौबे हैं। विश्वविद्यालय के डीन डॉ. योगेंद्र चौबे थिएटर फैकल्टी के हैड है। वे शहर से बाहर थे तो उनसे दूरभाष पर बात ही हो पाई। यह मेरे लिए सुखद था कि डॉ चौबे ने मेरे ऑडिटोरियम परिसर पहुंचने के पहले ही उन प्रोफेसर प्रशासन को मेरे आने की जानकारी दे दी थी। प्रोफेसर प्रशासन प्रशांत मलतियार ने विश्वविद्यालय के बारे में तमाम जानकारी देने के उपरांत बताया कि उस वक़्त वहां भारत रंग महोत्सव आयोजित हो रहा है।

वीरेंद्र बहादुर सिंह और उनकी पत्नी रानी पद्मावती देवी ने संगीत में बहुत रुचि रखने वाली अपनी पुत्री इंदिरा की मृत्यु के पश्चात वर्ष 1956 में इस विश्वविद्यालय को स्थापित किया था। भारत रंग महोत्सव में विभिन्न भाषा के नाटकों का मंचन देख मैंने पृष्ठ लिया कि छत्तीसगढ़ क्षेत्र के दर्शकों को क्या विभिन्न भाषाओं के नाटकों को देखने में रुचि रही है तो प्रोफेसर प्रशांत ने बताया कि लोगों ने नाटकों का भरपूर आनंद लिया है। विश्वविद्यालय के कुलपति सत्यनारायण राठौर ने आयोजन के प्रथम सत्र में ही यह कहा था कि भाषा की कोई बाधा नहीं आएगी और लोग देखकर ही नाटकों को समझ सकेंगे। परिसर में उपस्थित लोगों से बात करने पर यह लगा कि विभिन्न भाषाओं में नाटकों की प्रस्तुति में भी दर्शकों की भरपूर उपस्थिति बनी रही। लोगों को नाटकों का आनंद लेने में भाषा किसी तरह से बाधा नहीं बन पाई और इस तरह भाव भंगिमा प्रस्तुति तथा वेशभूषा नाट्य कलाकारों और दर्शकों के बीच संवाद स्थापित करती रही।

भारत रंग महोत्सव के तहत 4 से 9 फरवरी तक असमिया, बांग्ला, मराठी, तमिल, हिंदी आदि भाषाओं के नाटकों का मंचन विभिन्न राज्यों से आए कलाकारों द्वारा किया गया। प्रोफेसर प्रशांत ने बताया कि विश्वविद्यालय के डीन डॉ. योगेंद्र चौबे राष्ट्रीय नाटक



अकादमी से कोर्स करने वाले छत्तीसगढ़ के पहले व्यक्ति हैं। उन्होंने 2005 में दिल्ली से कोर्स किया था और छत्तीसगढ़ी लोकनाट्य की दृष्टि से पाहटिया, बहादुर कलारिन, रानी दाई, पाखंडी और पंचलाइट जैसे उनके कई नाटक प्रसिद्ध हैं।

छत्तीसगढ़ी भाषा के नाटकों का क्या भविष्य है और छत्तीसगढ़ के लोक कला मंचों पर छत्तीसगढ़ी भाषा के नाटकों की किस तरह की उपस्थिति है यह जानना भी दिलचस्प है। विश्वविद्यालय परिसर के बाहर आने पर नगर के भीतरी भाग में जहां एक स्थान पर गिटार यंत्र की प्रतिकृति के साथ संगीत नगरी खैरागढ़ देखने को मिली तो वही नगर के प्रवेश द्वार पर भी संगीत नगरी खैरागढ़ स्वागत करती है। यही नहीं भीतरी गलियों में भी इस नगर की पहचान के अनुरूप कई जगह वाद्य एवं गीतों स्वंलहरियां सुनाई दी। पता चला कि यहां पर संगीत सीखने के लिए भी कई लोग क्लासेस चलते हैं। इससे लगा कि खैरागढ़ और संगीत एक दूसरे के पूरक हैं। यह नगर संगीत से सरोबार है। निश्चित ही यह नगर अपने यहां संगीत विश्वविद्यालय होने का हक रखता है। विश्वविद्यालय की प्रस्तुति की उपलब्ध को गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी रेखांकित किया जा रहा है। यह इस संगीत नगरी के आकाश पर एक और चमकीला सितारा होगा।

जीव प्रेमियों को मिल सकती है जीव संरक्षण का आधार..



नर्मदापुरम। नगर का एक अकेला गोलू फोटो वाला हर दिन नर्मदा किनारे से कुछ अजीब लेकिन नई तस्वीर सुबह सुबह दिखाकर दिमाग झकझोर देता है जब अधिकांश अपने बिस्तर से नहीं उठ पाते उस समय गोलू भाई नर्मदा किनारे टहलकर सोशल मीडिया पर कुछ-न-कुछ सोचने-समझने के लिए तस्वीर परोस चुके होते हैं। फोटोग्राफी की इतनी पकड़ किसी दूसरे में देखने को नहीं मिली..? नर्मदा किनारे होने वाली हलचल को पहचान कर उसे लोगों तक पहुंचाकर सचेत करना जैसे जिम्मेदारी मानते हैं, अब आगे जिम्मेदारों का काम जैसे उन्होंने आज एक मृत कछुआ खूबसूरती से कैद कर प्राणि शास्त्रियों को इस विषय पर सोचने का विषय दे दिया। नर्मदा में पलने वाले जीव-जंतु बड़ी मात्रा में तो है लेकिन उन्होंने संरक्षण मिल पाना कठिन, किसी समय नर्मदा में बड़ी मात्रा में कछुए जिन्हें सामान्य बोलचाल में पातल भी कहते थे बड़ी मात्रा में मिला करती थी जो अब नहीं। आज अचानक उसका छोटा स्वरूप देख महसूस किया जा सकता है बनने वाले नर्मदा लोक के साथ विलुप्त हो रहे जीव जंतुओं के संरक्षण का काम भी किया जा सकता है। यह शायद उसकी पहल हो, सोशल मीडिया पर इसे लेकर काफी प्रतिक्रिया देखने मिल रही।

कृष्ण भक्ति का प्रचार किया



नर्मदापुरम। एलआईसी दफ्तर के उपर द्वितीय तल स्थित इस्कॉन मंदिर परिवार कृष्ण भक्तों ने ग्राम विद्या कार्यक्रम के तहत आज पालनपुर ग्राम में कृष्ण भक्ति का प्रचार किया। परिवार के मुखिया प्रणव दास प्रभु के सानिध्य में ग्राम वासियों ने हरिनाम संकीर्तन करते हुए पूरे ग्राम में भगवान् कृष्ण की प्रसन्नता के लिए संकीर्तन करते हुए गलियों में भ्रमण किया। ग्रामवासियों ने अंत में प्रणव दास प्रभु के प्रति आभार व्यक्त करते हुए सभी कृष्ण भक्तों को फिर ग्राम आकर हरिनाम संकीर्तन करने आमंत्रित किया है।

मंत्री सिंह ने ली शिक्षा विभाग की बैठक

नरसिंहपुर। प्रदेश के परिवहन एवं स्कूल शिक्षा मंत्री श्री उदय प्रताप सिंह ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ विभाग की समीक्षा बैठक रविवार को सर्किट हाऊस नरसिंहपुर में ली। बैठक में तैदुखड़ा विधायक श्री विधनाथ सिंह पटेल, कलेक्टर श्रीमती शीतला पटेल, पुलिस अधीक्षक श्रीमती गंगाध्वी डेका, सीईओ जिला पंचायत श्री दलीप कुमार मौजूद थे। बैठक में मंत्री श्री सिंह ने कहा कि जिले में शिक्षा के स्तर को और बेहतर बनाना है। इसके लिए सभी बीईओ व बीआरसी स्कूलों का नियमित निरीक्षण अनिवार्यतः करें। इसकी मॉनिटरिंग के लिए जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिये कि वाटरसप रफ्त तैयार करें, जिसमें प्रतिदिन की गतिविधियों को अपडेट और निरीक्षण की रिपोर्ट प्रस्तुत की जाये। शिक्षा में कोताही किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं की जायेगी। शिक्षा का दायरेदार आप पर है। स्कूलों में शिक्षकों की नियमित उपस्थिति हो। लापरवाही करने वाले शिक्षकों के विरुद्ध सख्ती से कार्रवाई सुनिश्चित करें। बैठक में मंत्री श्री सिंह ने जिले में एफएलएन ट्रेनिंग की भी जानकारी ली। बैठक में मंत्री श्री सिंह ने हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी की बोर्ड परीक्षाओं की तैयारियों की भी जानकारी ली। इसमें जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया कि माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल अंतर्गत हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी की बोर्ड परीक्षाओं के लिए जिले में कुल 87 परीक्षा केन्द्र निर्धारित किये गये हैं। इन परीक्षा केन्द्रों पर कक्षा 10 वीं के 15 हजार 47 एवं कक्षा 12 वीं में 12 हजार 295 सहित कुल 27 हजार 342 परीक्षार्थी बोर्ड परीक्षाओं में शामिल होंगे। सर्किट हाऊस में आयोजित इस बैठक में पं. रामसेही पाठक, जिला शिक्षा अधिकारी श्री अनिल व्योहार, डीपीसी श्री आरपी चतुर्वेदी, समस्त बीईओ, बीआरसी, बीएस्री और अन्य अधिकारी भी मौजूद थे।

जिले में 4 परीक्षा केन्द्रों में दो सत्रों में आयोजित हुई राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा

नरसिंहपुर। जिले में मप्र लोक सेवा आयोग इंदौर द्वारा राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा रविवार 16 फरवरी को 4 परीक्षा केन्द्रों में दो सत्रों में परीक्षा सम्पन्न हुई, जिसमें पहला सत्र प्रातः 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक एवं द्वितीय सत्र दोपहर 2.15 बजे से सायं 4.15 बजे तक आयोजित की गई। प्रथम एवं द्वितीय सत्रों में 1167 परीक्षार्थियों में से प्रथम सत्र में 980 परीक्षार्थी उपस्थित व 187 अनुपस्थित और द्वितीय सत्र में 963 परीक्षार्थी उपस्थित व 204 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा शासकीय नेहरू उच्चतर माध्यमिक शाला नरसिंहपुर में प्रथम एवं द्वितीय सत्र में 300 परीक्षार्थियों में से प्रथम सत्र में 259 उपस्थित व 41 अनुपस्थित और द्वितीय सत्र में 254 उपस्थित व 46 अनुपस्थित रहे। शासकीय पॉलीटेक्निक कॉलेज नरसिंहपुर में प्रथम एवं द्वितीय सत्र में 250 परीक्षार्थियों में से प्रथम सत्र में 211 उपस्थित व 39 अनुपस्थित और द्वितीय सत्र में 204 उपस्थित व 46 अनुपस्थित रहे। शासकीय श्याम सुंदर नारायण मुरारान महिला कॉलेज नरसिंहपुर में प्रथम एवं द्वितीय सत्र में 300 परीक्षार्थियों में से प्रथम सत्र में 244 उपस्थित व 56 अनुपस्थित और द्वितीय सत्र में 242 उपस्थित व 58 अनुपस्थित रहे। इसी तरह शासकीय एमएलबी कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नरसिंहपुर में प्रथम एवं द्वितीय सत्र में 317 परीक्षार्थियों में से प्रथम सत्र में 266 उपस्थित व 51 अनुपस्थित और द्वितीय सत्र में 263 उपस्थित व 54 अनुपस्थित रहे।

विद्यालय में समाज की सहभागिता

नरसिंहपुर। विगत दिनों विकासखंड नरसिंहपुर अंतर्गत शासकीय विद्यालय में समाज की सहभागिता से छत्र छात्राओं के लिए शैक्षणिक से लेकर अन्य जीवन आधारणी संसाधन सामाजिक फंड द्वारा विद्यालयों को भेंट किए जा रहे हैं जो विद्यालय की बेहतरी में समुदाय को जोड़ने में जनपद शिक्षा केंद्र नरसिंहपुर के सतत प्रयास का परिणाम है। जिसके तहत शासकीय हायर सेकेण्डरी विद्यालय भैसापाला, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मुराड़, शासकीय नवीन माध्यमिक विद्यालय धुवफट गोंडी , माध्यमिक विद्यालय खापा धमना में आई डी बी बैंक द्वारा सी एस आर मद से शाखा प्रबंधक अर्जुन दागी, सहायक प्रबंधक सिद्धार्थ दक्षित , अकाउंट सेक्शन शाखा प्रबंधक अतुल मिश्रा,बी ए सी ब्रजेश नेमा द्वारा विद्यालय पहुंचकर वॉटर कूलर भेंट किए गए।

जनपद

मोदीजी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने शून्य कर स्लैब 2.5 लाख से 12 लाख किया: कविता पटीदार

स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी भाजपा की सरकार लगातार काम कर रही है, आम बजट 2025-26 विकसित भारत की और बढ़ते कदम ...

धार। भारतीय जनता पार्टी ने रविवार को केंद्रीय बजट पर पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इसमें मुख्य वक्ता भाजपा प्रदेश महामंत्री एवं राज्यसभा सांसद सुश्री कविता पाटीदार ने बजट के मुख्य प्रावधानों पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि इस बजट में विकसित भारत के साथ आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने शून्य कर स्लैब को बढ़ाकर 2.5 लाख से 12 लाख किया है, जिससे मध्यम वर्ग को अपूर्व लाभ होगा। सरकार का बजट हर वर्ग की वचत और आय बढ़ाने वाला है। पत्रकारवार्ता के दौरान धार भाजपा जिला अध्यक्ष महंत निलेश भारती, ग्रामीण जिला अध्यक्ष चंचल पाटीदार, विधायक कालु सिंह ठाकुर जिला पंचायत अध्यक्ष सरदार सिंह मेड़्रा प्रदेश मंत्री जयदीप पटेल ,भाजपा जिला मीडिया प्रभारी संजय शर्मा एवं सह मीडिया प्रभारी दीपक सिंह खुवंशी उपस्थित रहे।

विकसित भारत के साथ आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना वाला बजट- पत्रकारों से चर्चा करते हुए मुख्य वक्ता कविता पाटीदार ने बताया कि मध्यम वर्ग के लिए वर्ष 2014 में आय पर शून्य कर स्लैब ढाई लाख रुपये था, जो 2019 में 5 लाख और 2023 में 7 लाख किया गया। इस वर्ष के बजट में इसे 12 लाख कर दिया गया है। इससे मध्यम वर्ग को अपने दायित्व निभाने में काफी मदद मिल जाएगी। सरकार ने देश के युवाओं के भविष्य के लिए मध्यम वर्ग को सर्वाधिक महत्व दिया है। आयकर स्लैब के अलावा कई अन्य बजट प्रावधान भी इस वर्ग के विकास को प्रशस्त करने वाले हैं। उन्होंने बताया कि पिछले सप्ताह ही लोकसभा में नया आयकर अधिनियम भी पेश किया गया है। उसमें कई धाराओं को बदल गया है और इसका सरलीकरण किया गया है।



सुश्री पाटीदार ने कहा कि पूरी दुनिया के अंदर अर्थव्यवस्था में कमजोरी पर आ रही है, लेकिन हम 7 प्रतिशत से ज्यादा ग्रोथ रेट से आगे बढ़ रहे हैं और इस ग्रोथ रेट में बहुत सबसे बड़ा योगदान एमएसएमई का है। इसे बढ़ावा देने के लिए ढाई करोड़ तक के उद्योगों को अब सूक्ष्म माना जाएगा, जबकि पहले इसकी एक करोड़ तक की सीमा थी। इसी प्रकार 10 करोड़ तक लघु माने जाने वाले उद्योगों को 25 करोड़ किया गया है और 10 से 50 करोड़ तक के जो मध्यम उद्योग कहलाते थे, उन्हें 125 करोड़ तक कर दिया गया है।

मध्य प्रदेश को मिला बजट में विशेष प्रोत्साहन है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में ऐतिहासिक कदम- मध्य

प्रदेश में 2000 नई मेडिकल सीटों का प्रावधान किया गया है, जिससे हमारे प्रदेश के विद्यार्थियों को चिकित्सा शिक्षा के अधिक अवसर मिलेंगे। सड़क अधोसंरचना को बढ़ावा देते हुए 12,000 करोड़ की राशि सड़क निर्माण के लिए आवंटित की गई है, जिससे प्रदेश की कनेक्टिविटी और व्यापारिक गतिविधियां और सशक्त होंगी।कृषि और किसानों के लिए बड़ा समर्थन- धन-धान्य कृषि योजना से प्रदेश के हजारों किसानों को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा। एमएसएमई और स्टार्टअप को बढ़ावा देते हुए क्रेडिट गारंटी योजना और सूक्ष्म उद्यमों के लिए विशेष वित्तीय सहयोग प्रदान किया जाएगा। कुशल श्रम शक्ति और रोजगार आत्मनिर्भर भारत के लिए सक्षम

अवैध धंधे से जुड़े शख्स एक तरह से पुलिस का मुखबिर है, फिर इस मामले में नाकामी क्यों...?

नर्मदापुरम- संजीव डे राय। शनै:शनै: दो सप्ताह यानी 14 दिन समाप्ति पर आ निकले विप्र समाज सभी जिम्मेदारों की चौखट पर अमित दीवान आत्महत्या के मामले में न्याय पापे के लिए माथा ठेक चुके पर आईपीएल सट्टेबाजी के नाम दर्ज आरोपी पुलिस को ढूँढ नहीं मिल रहे । कहते हैं कि पुलिस अपराधी को पाताल से ढूँढ लाती है लेकिन इस मामले में ऐसा यहाँ कुछ दिखाई नहीं देता। कहा जा रहा है पुलिस आरोपियों की अग्रिम जमानत के लिए उनके अभिभावकों को उच्च न्यायालय जाने का मौका दे रही है। निचले अदालत ने जिनकी अग्रिम जमानत खारिज कर दी। दिखावे के लिए पुलिस ने जरूर नामजद आरोपियों पर ईनाम तक घोषित कर दिया। ऐसे में सवाल यह भी उठता है पुलिस इन आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए उनके प्रतिजनों को थाने क्यों नहीं बैठा ले ती.. फिर एक ही पुलिस चौकी पर पदस्थ वर्षों से पुलिस कर्मियों को तैनाती का पुलिस महकमे को ही क्या लाभ..? ऐसे तो इन्हें नगर के चप्पे-चप्पे में होने वाली सभी छोटी बड़ी घटनाओं की फल-फल की सटीक जानकारी होती है। लेकिन इन सट्टेबाजों का सुरूग नहीं..? आईपीएल सट्टेबाजी के गिराह हो जा जिसफरोशी का कारोबार, अवैध शराब बिक्री का मसला हो या परदं टोंगकर सट्टा लिखने का कारोबार, गांजे की खेप आने की खबर हो या चरस बिकने की, इन धंधे का जुड़ा हर व्यक्ति एक तरह से पुलिस का मुखबिर है, फिर इस मामले में नाकामी क्यों..? सामथारी आरोपियों को राजनीतिकों का संरक्षण है तो नगर आपराधिक तत्वों के हथों में खुला छोड़ दिया जायेगा..? मुख्यमंत्री योगीनाथ जी का कंधा बंटेंगे तो कटेंगे सोलह फीसदी यहाँ फिट बैठता है। विप्र समाज के

प्रतिनिधि हर जिम्मेदार की चौखट पर जरूर हाज़िर लगा रहा लेकिन विप्र समाज समाज चुनावी जीतने के सिवा फिर एक नहीं..। सुसाइड नोट के आधार पर देहात थाने में आकाश शिवहरे, विकी शिवहरे, ऋषि सराठे, भैयू सराठे, नितिन मालवीय, सोरभ शर्मा, विवेक ठाकुर, राकेश खुवंशी को एकआईआर में नाम दर्ज आरोपी बनाए है ।

कहां गए कांग्रेस और निर्दलीय प्रत्याशी...

अपनी मजबूती के लिए मतदाताओं का उपयोग करने वाले कांग्रेस और निर्दलीय प्रत्याशी की जरूरत आज विप्र समाज को ही नहीं पूरे विधानसभा क्षेत्र को है. विप्र समाज ने हालिया अपना युवा बच्चा खोया है और पूरे विधानसभा क्षेत्र की हालत ठीक नहीं। पूरे विधानसभा क्षेत्र में आईपीएल सट्टेबाजी, जुआ, सट्टा, शराब बिक्री, सरकारी जमीन पर अतिक्रमण पर हो रहा, युवा और व्यापारी वर्ग शराब और जुआ आईपीएल सट्टेबाजी की गिरफ्त में आ गया एक साल पहले कांग्रेस और निर्दलीय प्रत्याशी ने आम मतदाताओं से वोट मांगते वक्त उनके दुख-सुख में शामिल रहेंगे वायदा किया था..? फिर यह वादा निभाया क्यों नहीं जा रहा.. 57655 वोट लेकर निर्दलीय प्रत्याशी भावती चौरै और लगभग 33639 हजार वोट लेकर कांग्रेस उम्मीदवार गिरजा शंकर शर्मा इस मामले में धरम प्रदर्शन, चक्काजाम, आन्दोलन नहीं करके तो एक प्रकार से अपने मतदाताओं का अपमान ही कर रहे.. ऐसा क्यों..?

मध्यम वर्ग को राहत व भारत की अर्थव्यवस्था को ताकत देने वाला बजट - राव उदय प्रताप सिंह

नरसिंहपुर। भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय नरसिंहपुर में केन्द्रीय बजट 2025 - 26 को लेकर प्रेस वार्ता सम्पन्न हुई प्रेस वार्ता केबिनेट मंत्री राव उदय प्रताप सिंह भाजपा जिलाध्यक्ष रामसेही पाठक, जिला पंचायत अध्यक्ष ज्योति काकोडिया, विधायक विधनाथ सिंह पटेल, जिला महामंत्री डॉ.हरप्रभाद पटेल, ठाकुर राजीव सिंह, नंदकिशोर ठाकुर, नगर पालिका अध्यक्ष नीरज महाराज, जिला मीडिया प्रभारी अभिनव शर्मा, नगर अध्यक्ष अश्वल नेमा की उपस्थिति में सम्पन्न हुई। प्रेस वार्ता के पूर्व कार्यालय परिसर में स्थित पं.दीनदयाल उपाध्याय, श्यामप्रसाद मुखर्जी की मूर्तियों पर माल्यार्पण किया गया।प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने कहा कि सरकार द्वारा बजट में गरीब अन्न दाता युवा व नारी शक्ति के कल्याण एवं सशक्तिकरण हेतु बजट में घोषणाएं की गई है इस बजट में पुरानी योजनाओं को चालू रखा गया है वहीं नई योजनाओं के द्वारा समाज को

नई गति प्रदान की जावेगी। बजट में प्रत्येक वर्ग को ध्यान में रखकर घोषणाएं एवं उपलब्धियां इस प्रकार है -मध्यम वर्ग को राहत व अर्थव्यवस्था को ताकत देने वाला बजटभारत की अर्थव्यवस्था विश्व की समस्त देशों में सर्वाधिक तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है पिछले 10 वर्षों में मोदी सरकार के विकास और संरचनात्मक सुधारों ने अंतरराष्ट्रीय जगत का ध्यान भारत की ओर आकर्षित किया है। गरीब युवा अन्न दाता व नारी शक्ति पर ध्यान केन्द्रित करते हुए विभिन्न क्षेत्रों में विकास के कार्य प्रस्तावित किए गए है। मान.मोदी जी ने राष्ट निर्माण में मध्यम वर्ग के योगदान की शक्ति को पहचाना है। इसी कारण उन्होंने समय समय पर मध्यम वर्ग के कंधों से कर का बोझ कम किया है। इसी क्रम में उन्होंने पहले 2.50 लाख फिर 2019 में 5 लाख 2023 में 7 लाख और वर्तमान में 12 लाख तक की आय को कर मुक्त कर मध्यम वर्ग बहुत बड़ी राहत प्रदान करने का कार्य किया है।

मोदी सरकार का बजट किसानों,युवाओं,गरीबों और महिलाओं सहित सभी के हित में: सांसद महेन्द्र देवास

देवास ।नरेंद्र मोदी सरकार के 2025-26 के बजट को लेकर रविवार को शहर के रामाश्रय हॉल में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष रायसिंह सैंधव ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रस्तुत किया गया यह ऐतिहासिक बजट है, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और औद्योगिक क्षेत्र सहित विभिन्न क्षेत्रों के विकास का विशेष ध्यान रखा गया है। उन्होंने कहा कि यह बजट निर्धन, वंचित और मध्यम वर्गीय परिवारों सहित समाज के सभी वर्गों को लाभ पहुंचाने वाला है।

प्रदेश प्रवक्ता एवं सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रस्तुत इस बजट में देश की चार प्रमुख जातियों - गरीब, युवा, किसान और महिलाओं का विशेष ध्यान रखा गया है। प्रधानमंत्री की दृष्टि में यही चार वर्ग हैं, जिनका विकास ही देश की प्रगति का आधार बनेगा। उन्होंने कहा कि यदि इन चारों वर्गों को सशक्त किया जाता है, तो निश्चित रूप से 2047 में जब देश अपनी आजादी की 100वीं वर्षगांठ मनाएगा, तब भारत एक समृद्ध, शक्तिशाली और विकसित राष्ट्र होगा।

उन्होंने बताया कि भारत का बजट पहली बार 50 लाख करोड़ रुपये के पार पहुंचा है। इस बजट में कृषि और उससे जुड़ी योजनाओं को विशेष ध्यान दिया गया है। 1.71 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। भारत कृषि प्रधान देश है और इसीलिए कृषि की गुणवत्ता बढ़ाने, उत्पादन को दोगुना करने



और जलवायु के अनुकूल अधिक उपज देने वाले बीजों के विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है।

देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए इस बजट में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं। इसमें बड़े पुलों, रेलवे, परिवहन, फोरलेन सड़कों और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए व्यापक प्रावधान किए गए हैं। शिक्षा के क्षेत्र में भी विशेष ध्यान दिया गया है, जिसके तहत आईआईटी, आईआईएम, मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेजों के विकास के लिए 11.21 लाख करोड़ रुपये का बजट

आवंटित किया गया है।

सांसद सोलंकी ने कहा कि जब देश आजादी की 100वीं वर्षगांठ मनाएगा, तब भारत एक विकसित राष्ट्र बनना चाहिए। इसी दृष्टिकोण के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने यह बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के नेतृत्व में प्रस्तुत किया है। उन्होंने दोहराया कि इस बजट में गरीब, युवा, किसान और महिलाओं को केंद्र में रखा गया है, क्योंकि इन्हीं वर्गों के सशक्तिकरण से भारत की प्रगति सुनिश्चित होगी।

कार्यबल तैयार करने के लिए विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाएगा।

आर्थिक गतिविधियों में 70 प्रतिशत महिलाओं की भागीदारीमहिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना और महिलाओं को आर्थिक गतिविधियों में शामिल करना इस बजट का एक अहम हिस्सा है

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सौभाग्य से मध्यप्रदेश में उन्हें एमएसएमई विभाग की जिम्मेदारी दी है। विभाग कई दूर दृष्टि वाले कार्य कर रहा है। इसके तहत छोटे व्यापारी जो एमएसएमई का रजिस्टर्ड रहेगा उनको 5 लाख तक का एक कार्ड दिया जाएगा। यह जो कार्ड बजट में आया है इसका बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन लघु एवं मध्यम उद्योगों के लिए रहेगा। कृषि की दृष्टि से किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा 3 लाख से 5 लाख रुपए कर दी गई है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में कैसर की 35 दवाइयां से आयात शुल्क हटा दिया गया है। मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों की संख्या बढ़ाने के लिए इस वर्ष 10000 सीटें बढ़ाई जा रही है, और आने वाले 5 साल में यह संख्या एक लाख से दो लाख करने का लक्ष्य रखा है। धन-धान्य कृषि योजना के तहत 100 जिलों में 1.7 करोड़ किसानों को लाभ मिलेगा। किसान क्रेडिट कार्ड की ऋण सीमा 73 लाख से बढ़ाकर 75 लाख की जाएगी, जिससे 7.3 करोड़ किसानों को सीधा लाभ होगा।

सुश्री पाटीदार ने कहा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चिंतन रहा है कि जो विकास हो स्थाई हो और अनुदान आधारित नहीं हो। केंद्र का बजट इसी चिंतन का प्रतीक है, जो विकसित भारत के स्वप्न को पूर्ण करने में कारगर रहेगा। बजट के माध्यम से मोदी जी ने चार मंत्र दिए हैं कि गरीब, किसान, महिला और युवा यही चार जातियां हैं और इन चारों पर फोकस करके कार्य किया जाएगा।

यूथ हॉस्टल का आनंद उत्सव- मरू महोत्सव

मोहन वर्मा-देवास। यूथ हॉस्टल इंडिया एक ऐसी अखिल भारतीय संस्था है जो पर्यटकों को देशभर के दर्शनीय स्थलों से रूबरू करवाने,रोमांचक ट्रेकिंग करवाने और आकर्षक उत्सव-महोत्सव का आनंद लेने मे सेतु का काम करती हैं और इसी कड़ी में यूथ हॉस्टल इंडिया ने इस बार अपने सदस्यों को मरू महोत्सव जैसलमेर से रूबरू होने का अवसर दिया । 09 से15 फरवरी तक यूथ हॉस्टल के इसआयोजन में सदस्यों ने जैसलमेर मरू महोत्सव के आनंद के साथ टेंट स्टे जंगल सफारी,मृन् वाक का भी मजा लिया । यूथ हॉस्टल जैसलमेर इकाई की मेजबानी में इंदौर युनित के 28 सदस्यों के अलावा देश के



अलग अलग हिस्सों से आये 75 से अधिक सदस्य शामिल रहे । विश्व प्रसिद्ध मरू महोत्सव में पहले दिन दस फरवरी सुबह 9 बजे गड़ससर सरोवर से आकर्षक शोभायात्रा मुख्य बाजार से होते हुए निकली जो पुनम सिंह स्टेडियम पहुंची जहां मिस मूमल,मिस्टर डेजेंट ,मिसेज जैसलमेर,साफा बांधो,मूँछ प्रतियोगिता मूमल महेंद्र प्रतियोगिता का आयोजन हुआ जिसका सभी ने आनंद लिया । पपेट शो और मैजिक शो के बाद शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हसन खा, कुतले खान और सूफी सिंगर ज्योति नूरन की प्रस्तुति पर हजारों की संख्या में उपस्थित दर्शक झुमते रहे.

11 फरवरी गड़ससर सरोवर पर योगा विथ फॉक इंटरमेटेल ल्यूजिक के साथ हुआ और डेडानसर स्टेडियम में देशी कलाकारों ने प्रस्तुति दी । इसके बाद ऊंट श्रृंगार, शान ए मरुधरा ,एयरफोर्स के जवानों द्वारा ड्रिल शो,मस्कार रेस , जिम्मास्टमिक शो,केमल पोलो मैच , बीएसएफ द्वारा केमल टैटू शो हुए जो ये सब इतने शानदार हुए कि श्रोता मंत्रमुग्ध हो गए । इसी कड़ी में शाम को शहीद पुनम सिंह स्टेडियम में सांस्कृतिक कार्यक्रम में प्रसिद्ध पंजाबी गायक काका को भी श्रोताओं का भूषण प्यार मिला ।

12 फरवरी सुबह दामोदरा गांव में भूपू दौड़ प्रतियोगिता के साथ शाम को लखमाना के सुनहरे रेगिस्तान में केमल रेस का अनुपम आयोजन हुआ और माघ माह की पूर्णिमा को रेतोले धोरों में तगाराम भील, भुरारे खान के राजस्थानी लोकगीतों के साथ नीरज आर्या के कबीर कैफे बैंड द्वारा दी प्रस्तुतियो ने दर्शकों को झुमने पर मजबूर कर दिया ।

अगला दिन जैसलमेर की हवेलियों और फोर्ट के नाम रहा जहाँ पर्यटक राजस्थान के इतिहास से रूबरू होते रहे । दोपहर में पर्यटकों ने ऊंट की सवारी और जीप राइड के साथ रेतोले टीलों का आनंद लिया वहीं दोपहर में खाभा फोर्ट,शाम को कुलधरा के इतिहास से रूबरू हुए और रात जंगल में मून वॉक के साथ टेंट स्टे का मजा लिया ।

ग्रामीण विकास पर भी इस बजट में विशेष ध्यान दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मानते हैं कि भारत गांवों का देश है और ग्रामीण विकास के बिना संपूर्ण विकास संभव नहीं है। इसीलिए ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए 2.67 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जिससे गांवों में रोजगार के अवसर सृजित होंगे और पलायन को रोका जा सकेगा। इसके अलावा, शहरी विकास और परिवहन के लिए 6.45 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जिससे शहरों में आधुनिक बुनियादी ढांचे का निर्माण किया जाएगा। स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में भी बजट ने महत्वपूर्ण स्थान दिया है। यह सुनिश्चित किया गया है कि देश के प्रत्येक नागरिक को सुलभ और व्यापक स्वास्थ्य सुविधाएं प्राप्त हों और कोई भी शिक्षा से वंचित न रहे। इसके लिए 2.27 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

इन्फ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में इस बजट में विशेष निवेश किया गया है। इसमें रेलवे, परिवहन, फोरलेन सड़कों, पर्यटन और उच्च शिक्षा संस्थानों के विकास के लिए 11.21 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।मध्यम वर्ग को राहत देने के लिए आयकर में भी बदलाव किए गए हैं। अब 12 लाख रुपये तक की वार्षिक आय पर कोई कर नहीं लगेगा, जिससे मध्यम वर्ग को सीधा लाभ मिलेगा।इस अवसर पर बड़ी संख्या में पत्रकारण उपस्थित थे। संचालन धर्मेद चौधरी ने किया। अंत में आभार जिला सह मीडिया प्रभारी कमल अहिलवार ने माना।

प्रयागराज महाकुंभ 2025

रेल यात्रियों की सुविधा के लिए ट्रेनों के मार्ग परिवर्तित

भोपाल। रेल प्रशासन द्वारा परिचालनिक कारणों से भोपाल मंडल से गुजरने वाली कुछ यात्री गाड़ियों के मार्ग में परिवर्तन किया गया है, जिसका विवरण इस प्रकार है।

- गाड़ी संख्या 15017 लोकमान्य तिलक ट.-गोरखपुर एक्सप्रेस दिनांक 16.02.2025 एवं 17.02.2025 को अपने प्रारंभिक स्टेशन से प्रस्थान कर अपने निर्धारित मार्ग के बजाय परिवर्तित मार्ग वाया इटारसी-बीना-वीरगंगा लक्ष्मीबाई झाँसी-कानपुर सेंट्रल-लखनऊ-बाराबंकी होते हुए गंतव्य को जाएगी।
- गाड़ी संख्या 11071 लोकमान्य तिलक ट.-बलिया एक्सप्रेस दिनांक 16.02.2025 एवं 17.02.2025 को अपने प्रारंभिक स्टेशन से प्रस्थान कर अपने निर्धारित मार्ग के बजाय परिवर्तित मार्ग वाया बीना-वीरगंगा लक्ष्मीबाई झाँसी-कानपुर सेंट्रल-लखनऊ-जौनपुर-वाराणसी होते हुए गंतव्य को जाएगी।
- गाड़ी संख्या 22129 लोकमान्य तिलक ट.-अयोध्या कैट एक्सप्रेस दिनांक 16.02.2025 को अपने प्रारंभिक स्टेशन से प्रस्थान कर अपने निर्धारित मार्ग के बजाय परिवर्तित मार्ग वाया वीरगंगा लक्ष्मीबाई झाँसी-कानपुर सेंट्रल-लखनऊ-अयोध्या कैट होते हुए गंतव्य को जाएगी।
- गाड़ी संख्या 15018 गोरखपुर-लोकमान्य तिलक ट. एक्सप्रेस दिनांक 17.02.2025 एवं 18.02.2025 को अपने प्रारंभिक स्टेशन से प्रस्थान कर अपने निर्धारित मार्ग के बजाय परिवर्तित मार्ग वाया गोरखपुर-बाराबंकी-लखनऊ-कानपुर सेंट्रल-वीरगंगा लक्ष्मीबाई झाँसी-बीना-इटारसी होते हुए गंतव्य को जाएगी।
- गाड़ी संख्या 11072 बलिया-लोकमान्य तिलक ट. एक्सप्रेस दिनांक 17.02.2025 एवं 18.02.2025 को अपने प्रारंभिक स्टेशन से प्रस्थान कर अपने निर्धारित मार्ग के बजाय परिवर्तित मार्ग वाया वाराणसी-जौनपुर-लखनऊ-कानपुर सेंट्रल-वीरगंगा लक्ष्मीबाई झाँसी-बीना होते हुए गंतव्य को जाएगी।
- गाड़ी संख्या 22130 अयोध्या कैट-लोकमान्य तिलक ट. एक्सप्रेस दिनांक 17.02.2025 को अपने प्रारंभिक स्टेशन से प्रस्थान कर अपने निर्धारित मार्ग के बजाय परिवर्तित मार्ग वाया अयोध्या कैट-लखनऊ-कानपुर सेंट्रल-वीरगंगा लक्ष्मीबाई झाँसी होते हुए गंतव्य को जाएगी।

उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने बेला-सिलपरा बाईपास सड़क निर्माण कार्य का किया निरीक्षण

भोपाल। उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने निर्माणाधीन रीवा में बेला-सिलपरा बाईपास मार्ग का निरीक्षण किया। उप मुख्यमंत्री ने बाईपास मार्ग में बनाये जा रहे पुलों के निर्माण के संबंध में अधिकारियों को निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि बेला से सिलपरा बाईपास का निर्माण पूरा होने से रीवा शहर में रिंग रोड के दोनों भाग पूरे हो जायेंगे। जबलपुर तथा सतना की ओर से आने वाले एवं सीधी और



सिंगरौली जाने वाले वाहनों को बेला से सीधा मार्ग मिल जायेगा। बाईपास का निर्माण पूरा होने से रीवा में वाहनों का दबाव घटेगा। यह बाईपास रीवा के साथ-साथ सीधी और सिंगरौली जिले के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसके निर्माण कार्यों में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखें। निर्माण कार्य में किसी भी तरह की बाधा आने पर तत्काल प्रशासनिक अधिकारियों को अवगत करायें। बरसात से पहले बाईपास सड़क का निर्माण हरहाल में पूरा कराएँ। यह सड़क विन्ध्य में औद्योगिक विकास को गति देने में भी सहायक होगी। निरीक्षण के समय प्रभारी कलेक्टर डॉ. सीरभ सोनवड़े, तकनीकी अधिकारी तथा निर्माण एजेंसी के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव 24वीं अखिल भारतीय पुलिस वॉटर स्पोर्ट्स प्रतियोगिता का करेंगे शुभारंभ

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव सोमवार को 24वीं अखिल भारतीय पुलिस वॉटर स्पोर्ट्स प्रतियोगिता का शुभारंभ करेंगे। मध्यप्रदेश पुलिस की मेजबानी में 17 से 21 फरवरी तक भोपाल के बोट क्लब बड़ा बालाबग में प्रतियोगिता आयोजित होगी। प्रतियोगिता में 22 राज्यों, केन्द्र शासित प्रदेशों और केन्द्रीय सशस्त्र बलों के 557 प्रतिभागियों द्वारा सहभागिता की जायेगी। इसमें 132 महिला खिलाड़ी भी शामिल होंगी। प्रतियोगिता में मेजबान मध्यप्रदेश पुलिस के अलावा असम, मणिपुर, बिहार, उत्तरप्रदेश, उत्तराखण्ड, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, पंजाब, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, जम्मू एण्ड कश्मीर, ओडिशा, केरल, सी.आर.पी.एफ., एफ.एस.बी., बी.एस.एफ., असम राईफल्स, आई.टी.बी.पी., अण्डमान एवं निकोबार एवं चण्डीगढ़ की 22 टीमों के खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। पाँच दिवस तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में केनोइंग, क्याकिंग तथा रोगें का कुल 27 स्पर्धाएं होंगी। इसमें कुल 360 पदकों (पुरुष वर्ग में 60 स्वर्ण, 60 जूज और 60 कांस्य पदक एवं महिला वर्ग में 60 स्वर्ण, 60 रजत और 60 कांस्य) के लिये विभिन्न राज्य और अर्द्धसैनिक बलों की टीमें अपना जोहर दिखायेंगी। प्रतियोगिता के संरक्षक पुलिस महानिदेशक श्री कैलाश मकवाना और मुख्य आयोजन समिति के अध्यक्ष विशेष पुलिस महानिदेशक श्री विजय कटारिया, डायरेक्टर स्पोर्ट्स श्री रवि कुमार गुप्ता, आयोजक सचिव श्रीमती कृष्णावेणी देसावतु पुलिस महानिरीक्षक विसबल एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की अध्यक्षता में गठित विभिन्न समितियों द्वारा इस प्रतियोगिता को संपादित कराया जायेगा।

अपृहत 17 वर्षीय बालिका को जिला विदिशा से दस्तयाब किया

नरसिंहपुर। पुलिस द्वारा चलाया जा रहा आपरेशन मुस्कान, थाना पलोहा अंतर्गत अपृहत 17 वर्षीय नाबालिक बालिका को जिला विदिशा से दस्तयाब कर परिजनों को किया सुपुर्द। उल्लेखनीय है कि जिला अंतर्गत अपृहत नाबालिग बालिकाओं के प्रकरणों की समीक्षा उपरान्त नाबालिग बालिकाओं की पतासाजी कर दस्तयाब करने हेतु आपरेशन मुस्कान चलाया जाकर जिला अंतर्गत अपहरण के प्रकरणों में कार्यवाही हेतु विशेष टीमों का गठन किया जाकर लगातार कार्यवाही की जा रही है। 17 वर्षीय नाबालिक बालिका को जिला विदिशा से दस्तयाब कर परिजनों को किया सुपुर्द - * थाना पलोहा, जिला नरसिंहपुर के अपराध क्रमांक 181/23 धारा 363 भादवि के प्रकरण 17 वषीय अपहृता की तलाशी हेतु पुलिस द्वाय किये गये अथक प्रयासों के चलते दिनांक 14.02.2025 को ग्राम करैया हाट, चौकी खामखेडा, थाना करारिया, जिला विदिशा से सकुशल दस्तयाब कर उसके माता- पिता के सुपुर्द किया गया है।

राजधानी आसपास

एम्स भोपाल और सीएमएचओ भोपाल द्वारा मुस्कान पहल के तहत बाल चिकित्सा देखभाल पर ओरिएंटेशन एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन

भोपाल। एम्स भोपाल के कार्यपालक निदेशक प्रो. (डॉ.) अजय सिंह के मार्गदर्शन में, अस्पताल संक्रमण नियंत्रण समिति,एम्स भोपाल ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भोपाल के सहयोग से जिला अस्पतालों, सिविल अस्पतालों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में कार्यरत बाल रोग विशेषज्ञों, नर्सिंग अधिकारियों और फीडिंग प्रदर्शकों के लिए एक ओरिएंटेशन और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए, प्रो. (डॉ.) अजय सिंह ने स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा अनुभव की जाने वाली चुनौतियों पर चर्चा के लिए इंटरएक्टिव सत्रों के महत्व को रेखांकित किया और शिशु स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार के लिए नियमित प्रशिक्षण की आवश्यकता पर बल दिया। भोपाल के सीएमएचओ, डॉ. प्रभाकर तिवारी ने संक्रमण नियंत्रण और रोकथाम प्रथाओं पर केंद्रित 'मुस्कान



कार्यक्रम' में एम्स भोपाल के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने एम्स भोपाल की अस्पताल संक्रमण नियंत्रण टीम के प्रयासों की सराहना की, जिन्होंने इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रशिक्षक की भूमिका निभाई। यह प्रशिक्षण राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानकों के तहत आयोजित किया गया, जिसमें स्वास्थ्य कर्मियों को उन्नत देखभाल तकनीकों, उपयुक्त पोषण प्रथाओं, नवीनतम उपचार प्रोटोकॉल और संक्रमण नियंत्रण उपायों से अवगत कराया गया। इस पहल का उद्देश्य शिशु मृत्यु दर को कम करना और बाल चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाओं की समग्र गुणवत्ता में सुधार करना है। यह संयुक्त प्रयास एम्स भोपाल की प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जो क्षेत्र में बाल चिकित्सा देखभाल सेवाओं को सुदृढ़ करने और स्वास्थ्य सेवा वितरण में उत्कृष्टता लाने की दिशा में कार्य कर रहा है।

‘नक्शा’ कार्यक्रम शहरी भूमि रिकार्ड्स के निर्माण और प्रबंधन में लाएगा क्रांति

देश के 152 नगरों में 18 फरवरी से होगी शुरुआत

भोपाल (नप्र)। केन्द्रीय भूमि संसाधन विभाग ने डिजिटल इंडिया लैंड रिकार्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम के तहत 'नक्शा' कार्यक्रम शुरू किया है। इसका उद्देश्य शहरी भूमि रिकार्ड्स के निर्माण और प्रबंधन में क्रांति लाना है। साथ ही शहरी भूमि रिकार्ड्स के लिये एक सटीक और व्यापक भू-स्थानिक डेटाबेस तैयार करना है। यह कार्यक्रम हवाई और जमीनी सर्वेक्षणों को उन्नत जीआईएस तकनीक के साथ जुड़कर भूमि प्रशासन को बेहतर बनायेगा। संपत्ति स्वामित्व रिकार्ड्स को

आसान करेगा और शहरी योजनाओं को सुचारु रूप से संचालित करने में मदद करेगा। सटीक भू-स्थानिक डेटा से निर्णय लेने की प्रक्रिया बेहतर होगी, भूमि उपयोग योजना अधिक प्रभावी बनेगी और संपत्ति से जुड़े लेन-देन आसानी से किये जा सकेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ड्रोन की उड़ान के साथ 18 फरवरी को रायसेन जिले से नक्शा कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। साथ

ही प्रदेश में वाटरशेड यात्रा को हरी झण्डी दिखाकर शुभारंभ करेंगे। प्रदेश के पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल और राजस्व मंत्री श्री करण सिंह वर्मा भी कार्यक्रम के शुभारंभ समारोह में शामिल होंगे। नक्शा कार्यक्रम को देश के 152 नगरों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया जा रहा है, जिसमें मध्यप्रदेश के 9 जिलों के 10 नगर (शाहगंज, छनेरा, अलीराजपुर, देपालपुर, धार कोटी, मेघनगर, माखन नगर (बाबई), विदिशा, सांची, उन्हेल) भी शामिल हैं।

शिक्षा की बेहतरी के लिये स्कूलों का हो नियमित निरीक्षण

भोपाल (नप्र)। स्कूल शिक्षा एवं परिवहन मंत्री श्री उदय प्रताप सिंह ने कहा है कि शिक्षा की बेहतरी के लिये स्कूलों का नियमित निरीक्षण सुनिश्चित किया जाना चाहिये। इसके लिये जिला शिक्षा अधिकारी व्हाट्सअप ग्रुप तैयार करें, जिसमें प्रतिदिन की गतिविधियों का अपडेट और निरीक्षण की रिपोर्ट तैयार की जाये। मंत्री श्री सिंह रविवार को नरसिंहपुर में स्कूल शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। बैठक में तेन्दुखेड़ा विधायक श्री विश्वनाथ सिंह पटेल भी मौजूद थे।



मंत्री श्री सिंह ने कहा कि शिक्षकों के प्रशिक्षण का कैलेण्डर बनाया जाये और उसके अनुसार

प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाये। उन्होंने कहा कि लापरवाही बरतने वाले शिक्षकों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाये। **बोर्ड परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा-** स्कूल शिक्षा मंत्री श्री सिंह ने हाईस्कूल एवं हायरसेकेंडरी बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी की जानकारी ली। बैठक में बताया गया कि जिले में 87 परीक्षा केन्द्रों पर बोर्ड परीक्षा संचालित होंगी। जिले में इस वर्ष 27 हजार 342 परीक्षार्थी बोर्ड परीक्षा में शामिल होंगे। मंत्री श्री सिंह ने अधिकारियों को नकल रोकने की सख्त व्यवस्था करने के निर्देश दिये।

सड़कों के निर्माण को समय-सीमा में पूरा करें: लोक निर्माण मंत्री सिंह

भोपाल (नप्र)। लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने कहा है कि सड़कों के निर्माण को समय-सीमा में पूरा किया जाये। निर्माण कार्य में विलंब उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि टाइम एक्सपेंशन नियमों को अधिकारी सख्त बनाये। लोक निर्माण मंत्री श्री सिंह रविवार को इंदौर में इंदौर संभाग की विभागीय समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे।

मंत्री श्री सिंह ने विलंब से चल रहे निर्माण कार्यों पर नाराजगी जताई और समय सीमा निर्धारित करने तथा टाइम एक्सपेंशन नियमों को सख्त बनाने के निर्देश दिए। सभी कार्यों को निर्धारित समय में पूर्ण करने के लिए ठेकेदारों और अधिकारियों को कहा। बैठक में मंत्री श्री सिंह ने सभी अधिकारियों से कहा कि लोक निर्माण का अर्थ लोक कल्याण है और समाज में इंजीनियर एक महत्वपूर्ण घटक है। छेटा या बड़ कोई भी इन्फ्रास्ट्रक्चर कोर इंजीनियर की भूमिका के संभव नहीं है। इंजीनियर समाज की एक महत्वपूर्ण इकाई है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देश पर प्रदेश भर में चारों तरफ निर्माण कार्य चल रहे हैं, जिससे प्रदेश में प्रगति और विकास की ब्यार बह रही है। सभी अधिकारी अपने कार्य में गुणवत्ता लायें, कार्य को निर्धारित समय सीमा में पूर्ण करें। इंजीनियर साईट पर जाकर



फिजिकल मॉनिटरिंग करें और ठेकेदार भी अपने कार्य के पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ करें। आगामी सिंहस्थ को देखते हुये सभी निर्माण कार्यों में प्रगति लायें। श्री सिंह ने कहा कि जो अधिकारी या ठेकेदार निर्धारित समय पर गुणवत्तापूर्ण कार्य नहीं करेंगे। उसके खिलाफ कठोर कार्यवाही की जायेगी और जो समय पर अच्छा कार्य करेगा ऐसे अधिकारियों को पुरस्कृत और सम्मानित भी किया जायेगा। बैठक में जनप्रतिनिधियों और विभागीय अधिकारियों ने भी अपने महत्वपूर्ण सुझाव दिये।

लोक निर्माण मंत्री श्री सिंह ने मूसाखेड़ी चौराहे पर 6 लेन फ्लाय-ओवर पुल के निर्माण कार्य,क्रिस्टल आई.टी. पार्क चौराहे पर 6 लेन फ्लाय-ओवर पुल निर्माण का कार्य, सत्यनई चौराहे पर 6 लेन फ्लाय-ओवर पुल निर्माण, देवास नाका चौराहा पर 6 लेन

भोपालवासी बने ब्रांड एम्बेसडर- मंत्री सारंग

भोपाल (नप्र)। सहकारिता, खेल एवं युवा कल्याण मंत्री एवं बेस्ट के संरक्षक विश्वास कैलाश सारंग ने आगामी 24-25 फरवरी को भोपाल में होने जा रहे ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के संबंध में 'भोपाल एक सभी टीम-BEST' की बैठक लेकर अभी तक किये कार्यों की समीक्षा की। मंत्री श्री सारंग ने कहा कि यह शहरवासियों के लिये हर्ष का विषय है कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट भोपाल में आयोजित होने जा रही है। समिट के दौरान भोपालवासी ही अपने शहर के ब्रांड एम्बेसडर बनें। उन्होंने नागरिकों से आह्वान किया है कि समिट में देश-विदेश से आने वाले सभी अतिथियों का स्वागत 'अतिथि देवो भवः' की भावना के साथ हो। जिसमें एयरपोर्ट से लेकर मुख्य आयोजन स्थल व अतिथियों के ठहरने के स्थानों तक गुजरने वाले सभी मार्गों पर बसे घरों में रहवासी स्वयं ही रोशनी बनाएं एवं लाइटिंग से सजावट करेंगे। स्वीच्छुर और सामाजिक सकारात्मक छवि हमारे अतिथियों के सम्मक्ष बनें। मंत्री श्री सारंग ने बताया कि जीआईएस में आने वाले अतिथियों की सुविधा और स्वागत को लेकर शहर के विभिन्न संगठन-व्यापारी संघ, सामाजिक व शैक्षणिक क्लब, उद्योगपति, और प्रबुद्धजन-से श्रोत्र ही संवाद किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भोपाल की स्वच्छता, सुवर्तता और सुगम आवागमन को बनाए रखने के लिए सरकार के साथ सामाजिक संगठन मिलकर काम करें। इसके अलावा, जीआईएस के फराह-प्रसा था, उसके बाद से ही पुलिस टीम उसकी तलाश में उसके संभावित स्थानों पर दबिश दे रही थी, लेकिन वह हाथ नहीं आ रहा था।

मामला दर्ज होते ही हो गया था फरार

मामला दर्ज होने के बाद से ही आरोपी फरार हो गया था, उसके बाद से ही पुलिस टीम उसकी तलाश में उसके संभावित स्थानों पर दबिश दे रही थी, लेकिन वह हाथ नहीं आ रहा था।

पुलिस का कहना

इस मामले में सीएसपी मुरार राजीव जंगल का कहना है कि नौकरी के नाम पर ठगी करने वाले एक आरोपी को थाटीपुर थाना पुलिस ने पकड़ है। फिलहाल आरोपी से पूछताछ की जा रही है।

दो दोस्तों को नौकरी लगवाने का झांसा देकर की थी ठगी

ग्वालियर (नप्र)। ग्वालियर में नौकरी लगवाने के नाम पर दो दोस्तों से पांच लाख रुपए ठगी करने वाले आरटीओ एजेंट मुकेश पुत्र रामचरण मण्डलिया को थाटीपुर थाना पुलिस ने उस समय दुल्लपुर से पकड़ लिया, जब वह अपने घर जा रहा था। पकड़े गए आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज है। पुलिस ने अब उससे पूछताछ शुरू कर दी है। मामला दर्ज होने के बाद से ही आरोपी फरार हो गया था और पुलिस उसकी तलाश में दबिश दे रही थी। थाटीपुर थाना प्रभारी कमल किशोर पाराशर ने बताया कि सुचना मिली थी कि धोखाधड़ी के मामले में एक साल से पुलिस को चकमा दे रहा आरोपी मुकेश मंडलिया अपने घर आने वाला है। सूचना मिलते ही आरोपी को पकड़ने के लिए



एसआई बलराम मांडी, प्रधान आरक्षक राजवीर कौशल, राज विकास, प्रतोष करहिया, आरक्षक संतोष और दीपक को पहुंचाया। पुलिस ने न्यू विवेक नगर के पास दुल्लपुर पर घेराबंदी की,

क्योंकि दुल्लपुर से ही उसके घर विवेक नगर जाने का रास्ता है। कुछ देर के इंतजार के बाद आरोपी वहां से गुजरा तो पुलिस ने बगैर देर लगाए उसे हिरासत में ले लिया।

दो दोस्त बने थे शिकार- बताया गया है कि आरटीओ एजेंट मुकेश मण्डलिया का परिचय धर्मवीर जाटव व राजेश गौतम से था और वर्ष 2021 में मुकेश ने धर्मवीर व राजेश गौतम को आरटीओ में जॉब दिलाने के नाम से पांच लाख रुपए लिए थे और जब काफी समय बीत गया और उनकी जॉब नहीं लगी तो पहले ठगलाता रहा और फिर पैसे लौटाने से इनकार कर दिया था। जिस पर वर्ष 2024 में पीड़ित धर्मवीर और राजेश ने इसकी शिकायत थाटीपुर थाने में दर्ज कराई।



अम्बाजी शक्तिपीठ मंदिर, गुजरात

अम्बाजी शक्तिपीठ मंदिर देवी माँ अम्बा माता को समर्पित है। अम्बाजी माँ का मंदिर भारत के सबसे पवित्र और सबसे महत्वपूर्ण शक्तिपीठों में से एक है। यह गुजरात-राजस्थान सीमा के पास पालनपुर से लगभग 65 किलोमीटर और माउंट आबू से 45 किलोमीटर दूर है। अरासुर की अम्बिका गुजरात के सबसे प्राचीन शक्तिपीठों में से एक है। गुजरात और महाराष्ट्र में अम्बाजी उनका लोकप्रिय नाम है। हर साल लाखों श्रद्धालु अम्बाजी की यात्रा करते हैं, जो इसे एक महत्वपूर्ण मंदिर शहर बनाता है। यह 51 शक्तिपीठों में से एक है। राजसी अम्बा माता देवता प्रसिद्ध गम्बर पहवाड़ियों के ऊपर निवास करती हैं और इस स्थान की शासक देवी हैं।



के एसडीओ बघेल नहर का निरीक्षण करने पहुंचे थे। स्थानीय किसानों ने उनके सामने सिंचाई की समस्या रखी, तो वे भड़क गए और मारपीट और गाली-गलौज करने लगे। वीडियो सामने आने के बाद आरोपी अफसर को सस्पेंड कर दिया गया है।इधर, एसडीओ श्रीराम बघेल पर केवलारी थाने में केस भी दर्ज किया गया है।

किसान गिड़गिड़ाते रहे, अफसर गालियां देता रहा- किसान अफसर के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते रहे। लेकिन अफसर ने उनकी एक न सुनी। वीडियो सामने आने के बाद जल संसाधन विभाग के प्रमुख अभियंता विनोद कुमार देवड़ा ने एसडीओ श्रीराम बघेल को निलंबित कर दिया है। उन्हें जल संसाधन विभाग नर्मदापुरम में अटैच किया है।

पटवारी बोले- सत्ता अफसरों के सामने सरेंड़र- मप्र कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी ने एक्स पर लिखा कि सिवनी में जल संसाधन विभाग के सख्त ने किसान को पीटा और फिर कार की डिकी में ठूस दिया। चूँकि सत्ता अफसरों के सामने सरेंड़र हैं, इसीलिए किसान प्रताड़ित हैं!

ट्रक ने बाइक सवार को कुचला, मौत

राजगढ़ में 100 मीटर तक घसीटा, गाय को टक्कर मारकर भाग रहा था, पीछा कर रहे थे युवक

राजगढ़ (भोपाल) (नप्र)। राजगढ़ के एलएच-52 पर शनिवार शाम होटल संस्कृति के पास तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवारों को कुचल दिया। हादसे में एक युवक की मौके पर मौत हो गई, जबकि एक की हालत गंभीर है। ट्रकर से बाइक ट्रक के नीचे फंस गई, इसके बाद भी ड्राइवर ने ट्रक नहीं रोक़ा और बाइक को 100 मीटर तक घसीटता चला गया।

बताया जा रहा है कि ट्रक चालक ने इससे पहले गाय को टक्कर मारी थी। उसी का पीछा करते हुए बाइक सवार पहुंचे थे। पीछा करता देख ड्राइवर ने ट्रक की रफ्तार बढ़ा दी। बाइक सवारों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं रुका और बाइक सवार को कुचल दिया।

ट्रक का पीछा कर रहे थे बाइक सवार- हादसे में घायल सुरेंद्र भिलाळा (37) निवासी शिक्षक कॉलेजी ने बताया कि वह ईट भट्टे पर मजदूरी करता है। वह रात में ब्यावार नाके पर खड़ा था। तभी बाराद्वारी में रहने वाला उसका दोस्त जितेंद्र राठौर (28) बाइक से आया और बाइक पर बैठने को कहा। हम खिलतीचुर नाके की तरफ जा रहे थे।

मैंने जितेंद्र से पूछा कि हम कहाँ जा रहे हैं तो उसने बताया कि एक ट्रक गाय को टक्कर मारकर निकल रहा है, उसे रोकना है, जिसके बाद वह फोन पर किसी से बात करने लगा, जितेंद्र ने होटल संस्कृति के पास सड़क पर अपनी गाड़ी से ट्रक को रोकने की कोशिश की तभी उसने हमें बाइक सहित कुचल दिया।

प्रदेश के घोषित पवित्र क्षेत्रों में मदिरा दुकानें 1 अप्रैल से होंगी बंद

मप्र की नई आबकारी नीति वर्ष 2025-26 जारी

भापाल (नप्र)। मध्यप्रदेश का नई आबकारी नीति के अनुसार प्रदेश में घोषित पवित्र क्षेत्रों में मदिरा दुकानों को 1 अप्रैल 2025 से बंद कर दिया जाएगा। इनमें उज्जैन, ओंकारेश्वर, महेश्वर, मण्डलेश्वर, ओरछा, मैहर, चित्रकूट, दतिया, पन्ना, मंडला, मुलताई, मंदसौर, अमरकंटक, सलकनपुर, बरमान कला, लिंगा, बरमान खुर्द, कुंडलपुर, बांदकपुर शामिल हैं। नई आबकारी नीति के अनुसार 1 अप्रैल 2025 से इन क्षेत्रों में किसी भी प्रकार के वाइन आउटलेट के लाइसेंस जारी नहीं किए जाएंगे एवं उनके संचालन की अनुमति भी नहीं होगी।

नये जिलों में मदिरा दुकानों का संचालन एवं प्रशासन वहां के जिला कलेक्टरों के अधीन किया जाएगा। जनजातीय बंधुओं के हित में वाइन शॉप पर वाइन एवं हैरिटेज मदिरा का विक्रय किया जा



सकेगा। एयरपोर्ट काउंटर पर भी हैरिटेज मदिरा विक्रय की अनुमति रहेगी। किसी भी मदिरा दुकान के परिसर में मदिरापान की अनुमति नहीं होगी।

वर्ष 2024-25 के वार्षिक मूल्य में 20 प्रतिशत की वृद्धि उपांत वर्ष 2025-26 के लिए आरक्षित मूल्य का निर्धारण किया गया है। वर्ष 2025-26 में सर्वप्रथम वर्तमान वर्ष 2024-25

क अनुज्ञातधारया का नवानांकरण का अवसर प्रदान किया गया है। तदोपरांत लॉटरी आवेदन पत्र आमंत्रित किये जायेंगे। नवीनीकरण एवं लॉटरी आवेदन पत्र से जिले के आरक्षित मूल्य के 80 प्रतिशत अथवा उससे अधिक के राजस्व की प्राप्ति होने पर जिले को नवीनीकृत किया जावेगा। जरूरत पड़ने पर ई-टेंडर और ई-टेंडर कम ऑक्शन की पद्धति से निष्पादन किया जावेगा।

सभी मदिरा दुकानों पर प्वाइंट आफ सेल मशीनें- सभी मदिरा दुकानों पर प्वाइंट ऑफ सेल मशीनें स्थापित की जायेंगी, मशीन के माध्यम से समस्त प्रकार की मदिरा बोतल पर चस्पा एक्ससाइज एंडेहसिव लेबल (इंएल) को अनिवार्यतः स्कैन कर ही बिरलिंग एवं विक्रय किया जा सकेगा। जो व्यक्ति ब्लैक लिस्टेड है वह मदिरा दुकान /समूह के लिए आवेदन करने के लिए पात्र नहीं होगा।

प्रत्येक जिले में जिला निष्पादन समिति

नई आबकारी नीति के अनुसार प्रत्येक जिले में जिला निष्पादन समिति गठित की जाएगी। जिला निष्पादन समिति मदिरा दुकानों का विस्थापन कर जिले में अन्य स्थान पर विस्थापित दुकान खोलने, दुकान का पोटेंशियल क्षेत्र निर्धारित करने, दुकानों का आरक्षित मूल्य निर्धारण करने, मदिरा दुकानों के एकल समूह का गठन या पुनर्गठन करने, शासन निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार दुकानों का निष्पादन करने संबंधी सभी कार्य करेगी। अपरिहार्य परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए मदिरा दुकान बंद करने के लिए आबकारी आयुक्त प्रस्ताव दे सकेगे।

